https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'मजबूत है देश की अर्थव्यवस्था'

वर्ष-12, अंक-21 01-15 नवम्बर, 2017 (पाक्षिक) ₹20

गुजरात

वंशवाद बनाम विकास की लड़ाई

'वामपंथियों ने हिंसा की राजनीति को बढ़ावा दिया'

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव लहराया भाजपा का परचम

सरल जीएसटी - देश के लिए दीपावली का उपहार

अहमदाबाद में गुजरात गौरव यात्रा समापन बैठक का भव्य दृश्य। इनसेट: जनसमूह का हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, गुजरात मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी और उपमुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल

विशाल जनसमूह को सम्बोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

विशाल जनसभा को सम्बोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

तिरूवनंतपुरम, केरल में जनरक्षा यात्रा के समापन दिवस पर पदयात्रा करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह, केरल भाजपा अध्यक्ष श्री कुम्मनम राजशेखरन तथा अन्य वरिष्ठ भाजपा नेतागण

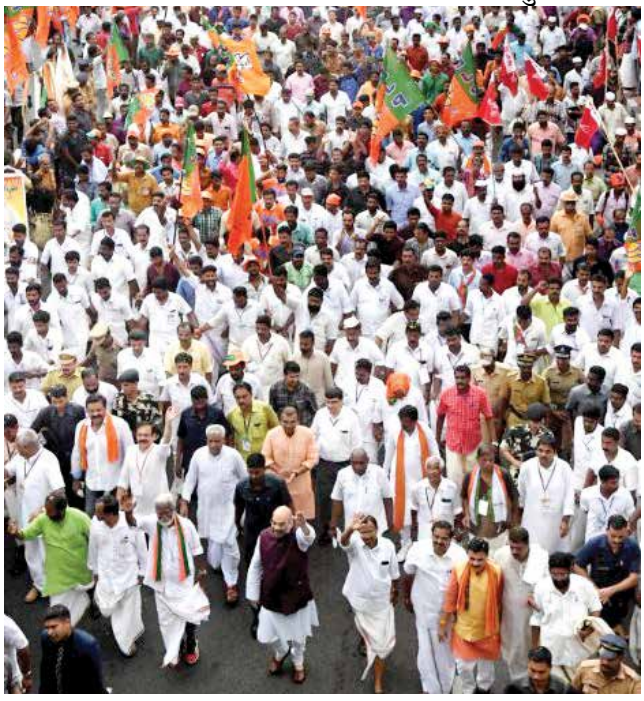

तिरूवनंतपुरम, केरल में विशाल जनसमूह को सम्बोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 'गुजरात गौरव महासम्मेलन' ने रचा इतिहास

एक पखवाड़े तक चली दो गुजरात गौरव यात्राओं के समापन और चुनावी विजय यात्रा के प्रारंभ के अवसर पर 16 अक्टूबर को राजधानी गांधीनगर में ऐतिहासिक गुजरात गौरव महासम्मेलन का आयोजन किया गया। यह भारतीय जनता पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा महासम्मेलन था। प्रधानमंत्री...

वैचारिकी

पटरियों पर बैठने वाले विक्रेताओं की समस्याएं 17

श्रद्धांजलि

'राजनीति के अजातशत्रु' कैलाशपति मिश्र 19

लेख

सरल जीएसटी - देश के लिए दीपावली का उपहार 20

केरल में साम्यवादी दमन अंत की ओर 22

अन्य

56,226 जल संचयन संरचनाएं और 1,13,976 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन 16

मजबूत है देश की अर्थव्यवस्था: नरेंद्र मोदी 24

'विमुद्रीकरण और जीएसटी का मंदी प्रभाव कमोबेश समाप्त' 28

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 4.9 प्रतिशत बढ़ा 29

'गांवों को स्वावलम्बी बनाने हेतु समर्पित थे नानाजी देशमुख' 30

500 रुपये का मासिक डीएसपीटी शुल्क 'शून्य' 31

'ज्ञान' और 'गंगा' दोनों से समृद्ध है बिहार: नरेन्द्र मोदी 32

स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04

पत्र-पत्रिकाओं से 33

स्फुट विचार 33

संगठनात्मक गतिविधियां

11 वामपंथियों ने हिंसा की राजनीति को बढ़ावा दिया: अमित शाह

आजादी के 70 साल बाद भी यदि कम्युनिस्ट पार्टी यह समझती है कि हम हिंसा से भाजपा...

13 1,311 सीटों पर लहराया भाजपा का परचम

महाराष्ट्र जिला पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत...

सरकार की उपलब्धियां

14 पहला अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस पर नई दिल्ली में अखिल...

15 जन धन खातों का असर: ग्रामीण इलाकों में ज्यादा हुई बचत

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना में से एक जनधन योजना का सकारात्मक प्रभाव...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

आयुर्वेद हमारा गौरव है। इससे स्वास्थ्य बेहतर के साथ ही तंदुरुस्ती सुनिश्चित होती है। हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क में आयुर्वेद को एकीकृत कर रहे हैं।

@AmitShah

कम्युनिस्ट विकास में विश्वास नहीं करते, जहां भी और जब भी कम्युनिस्टों ने शासन किया, वहां राजनीतिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं।

@rajnathsingh

नकली मुद्रा आतंक को वित्तपोषित करती है। एफआईसीएन और आतंक के वित्तपोषण के प्रवाह को रोकने में एनआईए प्रभावी भूमिका निभा रही है।

facebook

हमारी सरकार ने तय किया है कि 2020 तक राज्य में कोई बेघर न रहे। गरीब का सपना होता है कि उसके सिर पर छत हो, हमारी सरकार उस सपने को सच करेगी। इस कार्यसमिति में संकल्प लें कि झारखण्ड से गरीबी को समाप्त करना है, झारखण्ड को विकसित राज्य बनाना है। आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज्य दिया और अब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस राज्य को सजाने-संवारने का काम हो रहा है। — **रघुबर दास**

पिछले कई वर्षों से चली आ रही जातिवादी व्यवस्था को समाप्त करते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। प्रदेश सरकार का संकल्प है कि विकास कार्यों को उपेक्षित, वंचित तथा दबे कुचले लोगों के द्वार तक पहुंचाया जाये। — **योगी आदित्यनाथ**

विश्व खाद्य दिवस के मौके पर आइए, साथ मिलकर संकल्प लें कि ऐसा समाज बनाएंगे जहां किसी को भूखा न सोना पड़े और न ही भोजन की बरबादी हो। — **डॉ. रमन सिंह**

कमल संदेश

जन्मदिन **22 अक्टूबर**

कमल संदेश परिवार भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उन्हें शक्ति और असीम ऊर्जा से अभिभूत करे, ताकि वे भाजपा को और अधिक ऊंचाई पर ले जा सकें।

"सार्वजनिक जीवन की शुचिता को भी हम ऊंचा उठाकर एक ऐसा दबाव पैदा करें कि न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश के सभी राजनीतिक दल सार्वजनिक शुचिता के साथ सार्वजनिक जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाएं। ऐसा प्रण आज हम सबको लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि इस देश के सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई दे और ऊंचाई कोई उपदेश से नहीं दी जाती, कृतित्व से दी जाती है, स्वयं उस पर अमल करने से दी जाती है।

– अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा"

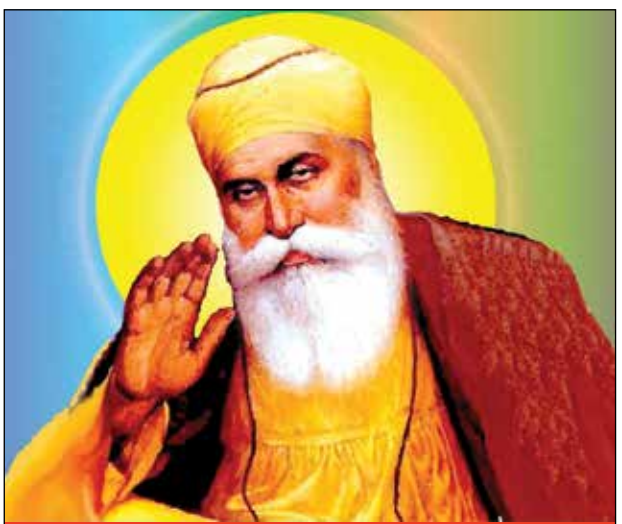

'कमल संदेश' की ओर से सुधी पाठकों को गुरुनानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं!

'निराशा की राजनीति' को झटका

जैसे–जैसे लोगों का कारवां 'गुजरात गौरव सम्मेलन' की ओर बढ़ता गया, वैसे ही वह एक जनसमुद्र में बदल गया। इस विशाल जनसमूह से गुजरात चुनावों का परिदृश्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया। जो लोग भाजपा को थोड़ा–बहुत भी चुनौती देना चाहते थे, उन्हें इस सम्मेलन में एकत्रित हुए लोगों ने अपना निर्णय सुना दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में गुजरात ने जो अद्भुत विकास किया है, उसका उदाहरण आज पूरे विश्व में दिया जा रहा है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भी लोग भारी संख्या में भाजपा के समर्थन में उतर रहे हैं। 'परफॉर्मेंस की राजनीति' तथा विकास की चाह आज कांग्रेस की वंशवादी, वोट बैंक तथा जातिवादी राजनीति पर भारी पड़ रही है। लोग अब मानने लगे हैं कि विकास ही वह मंत्र है, जिससे देश आगे बढ़ सकता है और नई ऊंचाइयां प्राप्त कर सकता है। लोगों के असीम स्नेह एवं प्यार से नरेन्द्र मोदी निरंतर वह ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे पूरे देश में विकास की लहर बहाने में वे सफल हो रहे हैं। यह उनकी दूरदृष्टि एवं कड़ी मेहनत का ही परिणाम है, जो आज देश उन स्वप्नों को साकार कर पा रहा है जो तीन वर्ष पहले देखना भी मुश्किल था। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व कांग्रेस शासन में जो देश भ्रष्टाचार, कुशासन एवं 'पॉलिसी पैरालिसिस' से ग्रस्त था, नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अद्भुत परिवर्तनों को देख रहा है।

कुछ समय पूर्व देश में अचानक कुछ लोग अर्थव्यवस्था के डूब जाने की भविष्यवाणी करने लगे। वास्तव में प्रधानमंत्री की राजनैतिक इच्छाशक्ति से जिस प्रकार के आर्थिक सुधार हुए, उससे कुछ लोगों की बढ़ती परेशानियों को समझा जा सकता है। जब जीएसटी को लागू करने की विशाल प्रक्रिया आरम्भ हुई तब इस महा–परिवर्तनकारी कदम में भी कुछ लोग आलोचना की संभावना तलाशने लगे। यह तो पहले से ही पता था कि इतने बड़े परिवर्तन से शुरुआती दिक्कतें आयेंगी और निरंतर इन दिक्कतों को आवश्यकतानुसार दूर कर सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता पड़ेगी। यह तो एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था की ओर जाने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज स्थिति यह है कि जो लोग अर्थव्यवस्था के डूबने की बात कर रहे थे, पूरी दुनिया में इस कदम की प्रशंसा से रटी–रटायी बातों से अधिक कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने जहां जीएसटी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की बात कही है, वहीं पिछली तिमाही में आर्थिक दर में आई कमी को जीएसटी लागू होने के कारण क्षणिक विक्षेप कहा है। लगभग ऐसी ही बात कहते हुए तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत आरोह की अपेक्षा करते हुए आइएमएफ प्रमुख क्रिस्टिन लेगार्ड ने कहा कि चूंकि बजट घाटा में कमी हुई है, मुद्रास्फीति नीचे है, इसलिए इस प्रकार के संरचनात्मक सुधारों से युवाओं को रोजगार मिलने की बड़ी संभावनाएं हैं। इसी प्रकार की आशा जताते हुए स्टानले मोर्गन ने कहा कि अगस्त में स्थिति सुधरने के साथ जीएसटी संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। लगभग हर प्रकार के रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ही सकारात्मक ढंग से देखा जा रहा है तथा व्यापक सुधारों के लिए प्रशंसा ही रही है।

> एक ओर आज जब नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा– आशा, कड़ी मेहनत, राजनैतिक इच्छाशक्ति तथा भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की संकल्पशक्ति के प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो देश को झूठे प्रापेगेंडा और पथभ्रष्ट तरीके से निराशा में डूबोना चाहते हैं।

एक ओर आज जब नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा–आशा, कड़ी मेहनत, राजनैतिक इच्छाशक्ति तथा भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की संकल्पशक्ति के प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो देश को झूठे प्रापेगेंडा और पथभ्रष्ट तरीके से निराशा में डूबोना चाहते हैं। ये वो लोग नहीं जो सार्थक आलोचना में विश्वास करते हैं बल्कि वे अपने क्षुद्र राजनैतिक स्वार्थ के लिए संदेह और संशय का वातावरण बनाना चाहते हैं। ये लोग यह नहीं समझ पा रहे कि निराशा की राजनीति का खेल जो ये खेल रहे हैं, उससे वे लगातार भारतीय राजनीति के हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। आज भारत एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर रहा है जो आत्मविश्वास से परिपूर्ण है तथा नरेन्द्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व में विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। चुनाव–दर–चुनाव लोगों का भारी समर्थन भाजपा के पक्ष में और भी अधिक मजबूती से दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में भी जनता कांग्रेस और इसके सहयोगियों को एक और कड़ा झटका देने को तैयार हैं। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

'गुजरात गौरव महासम्मेलन' ने रचा इतिहास

एक पखवाड़े तक चली दो गुजरात गौरव यात्राओं के समापन और चुनावी विजय यात्रा के प्रारंभ के अवसर पर 16 अक्टूबर को राजधानी गांधीनगर में ऐतिहासिक गुजरात गौरव महासम्मेलन का आयोजन किया गया। यह भारतीय जनता पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा महासम्मेलन था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री श्री विजय रुपानी सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस महासम्मेलन को संबोधित किया। गुजरात गौरव महासम्मेलन के लिए सजे गांधीनगर की रौनक देखते ही बनती थी। भाजपा के झंडों, बड़ी संख्या में लगे होर्डिंग्स और विविध तरीकों से सजावट ने पूरे शहर की फिज़ा बदल दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे गांधीनगर के सभी रास्ते महासम्मेलन के आयोजन स्थल की ओर ही बढ़ रहे थे। हर तरफ "हूं छुं विकास, हूं छुं गुजरात" के नारों से गांधीनगर गुंजायमान हो रहा था। ज्ञात हो कि पूज्य महात्मा गांधी के जन्मस्थान पोरबंदर और सरदार पटेल के जन्मस्थान करमसद से दो गुजरात गौरव यात्राएं समानान्तर पूरे गुजरात में जनजागरण करती हुईं 16 अक्टूबर को गांधीनगर पहुंचीं। इन यात्राओं ने 4,471 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 149 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। गुजरात गौरव यात्राओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाते हुए शुरू किया था। इन यात्राओं में ढाई सौ बड़ी सभाओं, स्वागतों और सम्बंधित कार्यक्रमों में लाखों लोग शामिल हुए। गुजरात गौरव महासम्मेलन आगामी विधानसभा चुनावों के हिसाब से प्रदेश के 50 हज़ार से अधिक बूथों के पन्ना प्रमुखों तक को जागृत करने का महाभियान था। इस महासम्मेलन के लिए 26 प्रवेश द्वार बनाये गए थे। लोगों की विशाल उपस्थिति को देखते हुए बैठने के लिए 72 ब्लॉक बनाए गए। 15 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई थी। महासम्मेलन की तैयारी में 10 हज़ार कार्यकर्ता विभिन्न समितियों के माध्यम से सक्रिय थे। महासम्मेलन स्थल तक विभिन्न चौराहों को सजाया गया, जहां हर जगह कल विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हुए। महासम्मेलन में पहुंचने वाले लोगों का अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया।

भाजपा विकास और केवल विकास में यकीन रखती है : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 16 अक्टूबर को गांधीनगर, गुजरात में एक पखवाड़े तक चली दो गुजरात गौरव यात्राओं के समापन और चुनावी विजय यात्रा के प्रारंभ के अवसर पर आयोजित ऐतिहासिक गुजरात गौरव महासम्मेलन को संबोधित किया और गुजरात की जनता से राज्य में विकास की गति और और तेज करने के लिए इस बार 150 से अधिक सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सम्बोधित करते हुए कांग्रेस की नीतियों एवं भ्रष्टाचार पर जम कर प्रहार किये। सम्मेलन में राज्य के कोने-कोने से आये लाखों कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था। सभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रुपानी, उप-मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू भाई वाघानी, गुजरात भाजपा के प्रभारी श्री भूपेन्द्र यादव एवं अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। ज्ञात हो कि श्री शाह ने विगत 01 अक्टूबर को लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पावन भूमि करमसद से और 02 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पोरबंदर से गुजरात गौरव यात्राओं की शुरुआत की थी।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सभा स्थल पर मेरी नजर जहां तक जा रही है, भाजपा ही भाजपा के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते दिनों एक टेलीविजन कार्यक्रम में मुझसे पूछा गया कि आप गुजरात विधानसभा चुनाव में 150 सीटें जीतने की बात किस आधार पर कह रहे हैं, लेकिन जो यह रैली देख रहे होंगे, वे समझ जाएंगे कि हम 150 से कहीं ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1990 से लेकर अब तक तक दो-तिहाई बहुमत से गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, लेकिन इस बार 2017 में गुजरात की जनता तीन-चौथाई बहुमत से हमें अपना आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि जब श्री नरेन्द्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो हमारी 127 सीटें आई थीं, अब वे प्रधानमंत्री हैं तो निश्चित तौर पर हमें 150 से अधिक सीटें आयेंगी।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस केवल चुनावों के समय ही गुजरात में दिखती है, इससे पहले कांग्रेस कहीं दिखती ही नहीं। चुनाव के वक्त दिखने वाली कांग्रेस काउंटिंग शुरू होते ही गायब हो जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल जीतेगी-जीतेगी, ऐसा कहती रहती है, लेकिन चुनाव में हर बार उसे करारी पराजय का सामना करना पड़ता है। कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ दो-तिहाई बहुमत के लिए नहीं लड़ना है, बल्कि कांग्रेस को समूल उखाड़ फेंकना है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 1995 से लेकर 2017 तक की गुजरात में हमारी यात्रा राज्य के विकास की यात्रा रही है। उन्होंने कहा कि सब कौतूहल से पूछते हैं कि गुजरात में विकास कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से गुजरात के

विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुए, गांवों में 24 घंटे बिजली पहुंची, शुद्ध पीने का पानी पहुंचा, सड़कों का नेटवर्क तैयार किया गया, उद्योग-धंधे विकसित किये गए, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर की गई, यह इसी का परिणाम है कि आज गुजरात विकास के नक्शे पर कहीं आगे दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने पहले मुख्यमंत्री और बाद में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए नर्मदा योजना की तमाम अड़चनों को दूर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात को बुलेट ट्रेन की सौगात दी, वहीं कांग्रेस इसकी आलोचना कर रही है। गुजरात की जनता मत के माध्यम से कांग्रेस को इसका माकूल जवाब देगी। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू-मुक्त, अपराध-मुक्त और रोजगार-युक्त गुजरात बनाने का काम श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि वाईब्रैंट गुजरात के माध्यम से राज्य में उद्योग और इन्वेस्टमेंट लाने का काम श्री नरेन्द्र भाई मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि चाहे साक्षरता दर हो, बिजली उत्पादन व उपभोग के आंकड़े हों अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात - हर क्षेत्र में श्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में गुजरात ने विकास

केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से देश में लगभग हुए हर चुनाव में कांग्रेस की भारी पराजय हुई है। कांग्रेस विकास विरोधी है, वह देश का विकास करना ही नहीं चाहती। कांग्रेस कितना भी प्रयास कर ले, वह भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे को हरा नहीं पायेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास और केवल विकास में यकीन रखती है।

की एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग में जब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, तब गुजरात को विकास के लिए शेयर इन सेन्ट्रल टैक्स, डिजास्टर रिलीफ, लोकल बॉडीज ग्रांट इत्यादि सेक्टर में केवल 63,346 करोड़ रुपए मिलते थे, जबकि आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 14वें वित्त आयोग में गुजरात को 1,58,377 करोड़ रुपये मिले हैं।

श्री शाह ने कहा कि गुजरात की विजय भाई रुपानी सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि गुजरात में किसानों को मिलने वाले कृषि ऋण पर ब्याज दर को शून्य कर दिया है, जो किसानों की भलाई की दिशा में गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय किसानों को 16% पर ऋण मिलता था, जिसे श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए घटाकर महज 1% कर दिया था, अब गुजरात की भाजपा सरकार ने किसानों को बिना किसी ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यही बताता है कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार किसानों के उत्थान के लिए किस तरह कटिबद्ध है। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस अपना कोई एक ऐसा राज्य बताये, जहां पर किसानों को इस तरह की सुविधा मिलती हो। श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कामरूप तक एक मजबूत संगठन के रूप में स्थापित हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में एक ही बात होती है कि नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल ही विकास का सर्वश्रेष्ठ मॉडल है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर करारा प्रहार करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं अभी चार दिन पहले ही अमेठी में कलेक्ट्रेट ऑफिस का भूमि-पूजन करके आया हूं। उन्होंने कहा कि 70 सालों तक जिन लोगों ने अमेठी का प्रतिनिधित्व किया, जो 70 सालों में अमेठी में एक कलेक्ट्रेट ऑफिस तक नहीं बनवा पाए, अस्पताल नहीं बनवा पाए, वे गुजरात में विकास का हिसाब मांग रहे हैं, इससे अधिक हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तो विकास पर कुछ भी बोलने का हक़ ही नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए पूछा कि कांग्रेस की तीन-तीन पीढ़ियां सत्ता में आईं, लेकिन नर्मदा योजना को क्यों कांग्रेस ने पूरा नहीं किया?

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई में आज देश के लगभग 80% भू-भागों पर भारतीय जनता पार्टी की लोक-कल्याणकारी सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से देश में लगभग हुए हर चुनाव में कांग्रेस की भारी पराजय हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास विरोधी है, वह देश का विकास करना ही नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितना भी प्रयास कर ले, वह भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे को हरा नहीं पायेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास और केवल विकास में यकीन रखती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे अंगद के पग की तरह पूर्ण निश्चय के साथ अडिग गुजरात और 'हूं छूं विकास, हूं छूं गुजरात' का संकल्प लेकर जनता के बीच में जाएं और भारतीय जनता पार्टी को तीन चौथाई बहुमत से विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 150 से अधिक सीटें जीतेगी और कांग्रेस का सफाया करेगी। ■

कांग्रेस में विकास के नाम पर चुनाव लड़ने का दम नहीं : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 अक्टूबर को गांधीनगर, गुजरात में एक पखवाड़े तक चली दो गुजरात गौरव यात्राओं के समापन और चुनावी विजय यात्रा के प्रारंभ के अवसर पर आयोजित ऐतिहासिक गुजरात गौरव महासम्मेलन को संबोधित किया और गुजरात की जनता से राज्य के विकास एवं भविष्य की मंगल कामना के लिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया।

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रतीक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग आपके ताकत को जानते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के सामर्थ्य और संकल्प से भली-भांति अवगत हूं। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में अनगिनत संकटों व झंझावातों का सामना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रहित एवं पार्टी के विकास के लिए कई आंदोलनों के माध्यम से देश भर में सत्याग्रह किया।

श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ वंशवाद में पली-बढ़ी पार्टियां हैं, तो दूसरी तरफ आदर्शों और विचारों को लेकर संकल्पबद्ध कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का इतना विशाल केसरिया महाकुंभ मैंने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का यज्ञ होता है और लोकतंत्र के सभी सिपाही एवं लोकतंत्र को आगे बढ़ाने वाले मतदाता इस यज्ञ के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत एवं पवित्र बनाने के उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं, लेकिन सतयुग और रामायण एवं महाभारत के कालखंड के समय से ही हम सुनते आए हैं कि जब

देश ने धनबल, बाहुबल और वंशवाद के बल पर चलनेवाली पार्टियों की कई सरकारें देखी हैं, लेकिन इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने शत-प्रतिशत लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी को चलाने का काम करके दिखाया है।

भी यज्ञ होता है तो रुकावट डालने वाले आते ही हैं। उन्होंने कहा कि सतयुग हो या कलयुग, यज्ञ में अड़चनें पैदा करने वाले तो आएंगे ही, लेकिन यज्ञ के प्रति समर्पित लोग संकल्पित होकर इस चुनाव यज्ञ को सफल बनाते ही रहेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने धनबल, बाहुबल और वंशवाद के बल पर चलनेवाली पार्टियों की कई सरकारें देखी हैं, लेकिन इसके

विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने शत-प्रतिशत लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी को चलाने का काम करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह को हार्दिक बधाई देता हूं। उन्होंने हिंदुस्तान के हर कोने में भाजपा के विजय ध्वज को फहराया है। 2014 के लोक सभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के परिणाम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त कहा था कि इस चुनाव के मैन ऑफ़ द मैच श्री अमित शाह हैं। उन्होंने कहा कि फिर उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव के परिणाम आये, भाजपा को इतनी बड़ी विजय प्राप्त होगी, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के परिणाम आये थे, राजनीतिक विश्लेषकों ने उसी दिन यह कह दिया था कि विपक्ष को 2019 का लोक सभा चुनाव भूल कर 2024 की चिंता करनी चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से गुजरात और गुजरात वासियों से भेदभाव करती आई है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नर्मदा योजना का शिलान्यास किया था, लेकिन यह योजना कांग्रेस को हमेशा चुभती थी क्योंकि इसकी कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसलिए इस योजना को कांग्रेस ने अधर में लटका कर रखा और तिस पर बेशर्मी से हमसे पूछते हैं कि नर्मदा योजना पूरी क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सरदार सरोवर की वजह से वो चिढ़ गए हैं, झूठ की भी कोई हद होती है, गुजरात के बच्चे-बच्चे को पता है कि नर्मदा के लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। पालीतणाका डैम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो पालीतणाका डैम में कैनाल के निर्माण का भी काम पूरा नहीं करा पाई। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नहर सिंचाई योजना शुरू की जिससे आज गुजरात के हर खेत में पानी पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकारों में 40 साल से प्रोजेक्ट लटके पड़े थे, क्योंकि काम पूरा करना इनके स्वभाव में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि संसद

में प्रोजेक्ट पास हो जाने के बावजूद 40 साल तक वे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही पड़े रहे, हमने ऐसे बंद पड़े 12 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स शुरू किए।

श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के जेहन में विकास के प्रति नफरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास विकास के मापदंडों पर लड़ने का साहस ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक ही चीज की आदत लगी है और वह है भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता, उनका परिवार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा रहा। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व और परिवार का मुखिया जमानत पर जेल से बाहर हों, वे गुजरात का विकास भला कैसे कर सकते हैं! उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जमानती पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस के मुखिया खुद जमानत पर बाहर हैं और भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर बाहर आए नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार को बचाना और वंशवाद को जिंदा रखना, यही कांग्रेस का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि मुझे गुजरात की जनता और उनकी दूरदर्शिता पर पूर्ण भरोसा है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस की स्थिति इतनी ही अच्छी थी, तो क्या कारण है कि उनकी पार्टी के 25% विधायक पार्टी

को छोड़ गए? उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकास के मुद्दे पर हमेशा से भागती रही है। उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि कांग्रेस कभी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े, लेकिन वे लगातार सांप्रदायिक जहर और जातिवाद के सहारे चुनाव लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि मुझे आशा थी कि इस बार कांग्रेस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बार फिर मैं इस मंच से कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि आइये और विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़िये, कांग्रेस को लोगों को भ्रमित करने का खेल बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव हमारे लिए विकासवाद की जंग है, जबकि कांग्रेस के लिए वंशवाद की जंग और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि एक बार फिर से विकासवाद जीतने वाला है और वंशवाद हारने वाला है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का जब कोई भी हथकंडा नहीं चला तो विकास को ही गाली देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि गांवों को सड़क नहीं चाहिए, बच्चों को स्कूल नहीं चाहिए और जनता को पानी और बिजली नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि ये विकास के बिना कैसे संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि नेहरू एक बार ज्योति संघ के कार्यक्रम में गए थे, लोग कहते हैं कि वहां वो ज्योति संघ भूल कर बार-बार जनसंघ बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का कांपना बहुत स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी हमें महात्मा गांधी का हत्यारा कहा, कभी शहरी पार्टी कहा, कभी दलित विरोधी पार्टी कहा, लेकिन कांग्रेस का कोई भी आरोप हम पर नहीं टिक सका। उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा दलित सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा आदिवासी सांसद भी भाजपा के हैं, सबसे ज्यादा किसान सांसद बीजेपी के हैं और जनता ने बार-बार कांग्रेस को नकार कर उनके आरोपों का पूरे ताकत से जवाब दिया है।

श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस GST को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी का निर्णय पार्लियामेंट अथवा प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि जीएसटी काउंसिल के सदस्य करते हैं, इसमें तो भारत सरकार का 30वां हिस्सा होता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने अकेले नहीं किया, बल्कि सभी राज्यों की सत्तारूढ़ दलों ने किया, कांग्रेस भी उसमें शामिल थी और इसलिए जीएसटी के नाम पर कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां झूठा प्रचार कर रही हैं। कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलने का कोई हक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में अगर कोई खामी है, तो यह सरकार जनता की सरकार है, वह उस खामी को दूर करने का प्रयत्न करेगी और हमने ऐसा किया भी है। जीएसटी के फायदों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से देश को फायदा होने वाला है और इससे एक राष्ट्र, एक देश का स्वप्न साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कांग्रेस को क्या तकलीफ है, दुख रहा है पेट और कूट रहे हैं सिर, नोटबंदी में उनके पैसे गए ना। उन्होंने कहा कि नोटबंदी में शेल कंपनियां पकड़ी गईं, 3 लाख करोड़ संदेह के घेरे में हैं, 2 लाख 10 हज़ार कंपनी को ताले लगा दिए। कोई हलचल नहीं हुई, केवल 5 हज़ार कंपनियों ने 15 दिन में चार हज़ार करोड़ बैंकों में जमा कराए, क्या यह पैसा गरीबों का नहीं था? उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आगामी 8 नवंबर को ब्लैक मनी से मुक्ति का पर्व, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी ब्लैक डे मनाएगी।

श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस में विकास के नाम पर चुनाव लड़ने का दम नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जवाब का सवाल मांगते हैं, इन्हें इतना पता नहीं कि सवाल पहले आता है। उन्होंने कहा कि सवाल का जवाब तो दे सकता हूं, लेकिन जवाब का सवाल कैसे दिया जा सकता है, जिन्हें ये समझ नहीं है, वे भला गुजरात का विकास क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि 6.5 करोड़ गुजराती का एक ही मंत्र होना चाहिए- हूं विकास छूं, हूं गुजरात छूं। ■

वामपंथियों ने हिंसा की राजनीति को बढ़ावा दिया: अमित शाह

आजादी के 70 साल बाद भी यदि कम्युनिस्ट पार्टी यह समझती है कि हम हिंसा से भाजपा एवं संघ की विचारधारा को रोक देंगे तो मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जितनी भी हिंसा करनी है, कर लीजिये लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को रोक नहीं सकते।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने केरल में भाजपा एवं विचार परिवार के कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हिंसक हमलों के खिलाफ विगत 03 अक्टूबर से जारी जनरक्षा यात्रा के 15वें व अंतिम दिन 17 अक्टूबर को परुथिप्परा से त्रिवेंद्रम तक पदयात्रा की।

जनरक्षा यात्रा के समापन अवसर पर त्रिवेंद्रम में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केरल में हिंसा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई अंत तक जारी रहेगी और भाजपा इसको जीत कर ही दम लेगी। सभा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री रामलाल एवं केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री के. राजशेखरन के अतिरिक्त कई गणमान्य नेता एवं संगठन पदाधिकारी उपस्थित थे। ज्ञात हो कि 15 दिनों तक चलने वाली जनरक्षा यात्रा की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 03 अक्टूबर, 2017 को की थी और उन्होंने पयान्नूर से पिलाथारा तक पदयात्रा का नेतृत्व भी किया था। 15 दिनों के दौरान जनरक्षा यात्रा ने 11 जिलों से गुजरते हुए 140 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और इस दौरान अलग-अलग समय इस यात्रा में लगभग सवा दो लाख लोग शामिल हुए, जबकि हजारों कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। जनरक्षा यात्रा के दौरान केरल के अलावे देश के सभी राज्यों की राजधानी में भी वामपंथी हिंसा के खिलाफ जनरक्षा यात्रा निकाल कर जनजागरण किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में विगत 4 अक्टूबर से कल 16 अक्टूबर तक हर दिन जनरक्षा यात्रा निकाली गई और हजारों की संख्या में लोग लाल आतंक के खिलाफ पदयात्रा में शरीक हुए। केरल में जनरक्षा यात्रा के दौरान हर दिन भाजपा के कोई-न-कोई मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री अथवा संगठन के पदाधिकारियों ने केरल के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पैदल मार्च किया और वामपंथी हिंसा के खिलाफ लोगों को एकजुट किया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जनरक्षा यात्रा को जो समर्थन केरल की जनता ने दिया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं उनको करबद्ध धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमें केरल में जनरक्षा यात्रा इसलिए निकालना पड़ा है, क्योंकि आजादी के 70 साल बाद भी राज्य में ऐसी स्थिति है कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं संघ के स्वयंसेवक अपने विचार व संगठन के विस्तार के लिए काम करते हैं तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 साल बाद भी यदि कम्युनिस्ट पार्टी यह समझती है कि हम हिंसा से भाजपा एवं संघ की विचारधारा को रोक देंगे तो मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जितनी भी हिंसा करनी है, कर लीजिये लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को रोक नहीं सकते। श्री शाह ने कहा कि मैं केरल के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि केरल की जनता ने वाम मोर्चे को क्या निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्या करने के लिए जनादेश दिया है?

श्री शाह ने कहा कि केरल में पिन्नाराई विजयन की सरकार बनने के इतने कम समय में ही भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 13 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याएं की जा चुकी हैं और सबसे

ज्यादा हत्या केरल के मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुई है। उन्होंने कहा कि मैं केरल के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप इन हत्याओं की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं या नहीं? उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि विजयन जी, यदि आपको स्पर्द्धा करनी है तो विकास की कीजिये, गरीबी को दूर करने की कीजिये, देश को आगे ले जाने के लिए स्पर्द्धा कीजिये, हिंसा की राजनीति के जरिये आप केरल में किस प्रकार की राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं?

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि केरल में वामपंथी पार्टियों द्वारा हिंसा कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां वामपंथी पार्टियों का लंबे समय तक शासन रहा, उन्होंने हिंसा की राजनीति को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि केरल में जब-जब वामपंथी पार्टियों की सरकार आई, राजनीतिक हिंसा व हत्याओं का दौर चला। उन्होंने कहा कि 1996 से 2001 के कालखंड में लगभग 30 लोग राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए, 2006 से 2011 के दौरान 28 लोग राजनीतिक हिंसा की बलि चढ़े और अब 2016 से आज तक 13 भाजपा एवं संघ कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या हो चुकी है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ केरल, बल्कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी, जहां भी वामपंथी पार्टियों की सरकारें लंबे समय तक

'अभी जो हमारे 13 कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, उनके परिजनों से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं इसके लिए जो भी दोषी हैं, उनमें से कोई बच न पाए, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी और जिन्होंने हिंसा की है, उनको सजा दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी।'

रही, वहां राजनीतिक हिंसा राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बनी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार एवं परिवारवाद के कारण देश से समाप्त हुई है तो कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक हिंसा के कारण। उन्होंने केरल की धरती से मार्क्सवादी पार्टी को आगाह करते हुए कहा कि अभी भी समय है, संभल जाइए वरना केरल की जनता भी आपको उखाड़ कर फेंक देगी।

श्री शाह ने कहा कि जब केरल और दिल्ली सहित देश भर में जनरक्षा यात्रा चल थी तब सीताराम येचुरी ने कहा कि राजनीतिक दल के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करना कितना उचित है। येचुरी जी, पहले आप अपने गिरेबां में झांक कर देखिये, हम तो शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी ने तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यालयों को बम से उड़ा दिया है, आपको बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 03 अक्टूबर को जनरक्षा यात्रा की शुरुआत के वक्त पर मैंने देश भर के ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस से अपील भी की थी और सवाल भी पूछा था कि देश में कोई भी छोटी सी घटना होती है तो आप कैंडल मार्च करने लगते हैं। केरल में पी. विजयन के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आते ही हमारे 13 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी गई है, तनिक उनके लिए एक भी प्रदर्शन तो कीजिये।

श्री शाह ने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट से जनता का ध्यान हटाना चाहती है और विकास पर जवाब देने के बजाय जनरक्षा यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि विजयन जी, जब भी आपको चर्चा करनी हो, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर हर वक्त चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केरल के विकास के लिए तीन साल में क्या किया है, मैं इसका जवाब अभी देने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस-नीत यूपीए की सरकार थी और जिसे वामपंथी पार्टियों का भी समर्थन प्राप्त था, तब केंद्र की यूपीए सरकार ने 13वें वित्त आयोग में केरल को 45,393 करोड़ रुपये की सहायता दी थी, जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने केरल को विकास के लिए 1,34,848 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई है जोकि कांग्रेस शासन के 13वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 89,000 करोड़ रुपये अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश में समान विकास एवं भेदभाव रहित राजनीति की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि विजयन जी, हम तो अपने कामकाज का हिसाब दे रहे हैं, लेकिन कल आप केरल की जनता को हमारे 13 निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्या पर भी जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा कि विजयन जी, हमें मालूम है, आपके पास इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं है, एक ओर देश भर में केरल में निर्दोष हत्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आपने इन्हीं 15 दिनों के दौरान हमारे कार्यकर्ता की हत्या के मुख्य आरोपी को एक ब्लॉक का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है, आपको शर्म आनी चाहिए!

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जनरक्षा यात्रा के प्रभाव से केरल के मुख्यमंत्री घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि विजयन जी के पहले केरल में कांग्रेस की सरकार थी तब सोलर स्कैम हुआ था, इसके लिए कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री ने ही एक कमीशन का गठन किया था, अब उस कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई है और उस रिपोर्ट में तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री और उनके साथियों पर जो आरोप सोलर स्कैम के तहत लगाए गए थे, उसे सही पाया गया है लेकिन जनरक्षा यात्रा निकलने के बाद विजयन जी पूर्व मुख्यमंत्री पर कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने प्रश्न पूछते हुए कहा कि विजयन जी, कांग्रेस के साथ आपकी ऐसी क्या डील हुई है जिससे आप त्वरित जांच के खिलाफ हो गए हैं? उन्होंने कहा कि आजादी के बाद हिंसा की राजनीति के सामने अब तक का सबसे बड़ा पैदल मार्च जनरक्षा यात्रा के रूप में निकला है, मैं इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई भी देता हूं और उनके हौसले की तारीफ़ भी करता हूं। ■

1,311 सीटों पर लहराया भाजपा का परचम

महाराष्ट्र जिला पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। दूसरे फेस में भाजपा ने 1311 स्थानों पर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस को 312 सीटें मिलीं। तीसरे नंबर पर शिवसेना रही, शिवसेना के खाते में 295 सीट आईं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 297 सीट मिलीं, वहीं अन्य के खाते में 453 सीटें आईं।

बता दें कि ग्राम पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में 7 और 14 अक्टूबर को हुआ था। पहले चरण की मतगणना 9 अक्टूबर को, जबकि दूसरे चरण की गिनती 16 अक्टूबर को हुई। दोनों ही चरणों में भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा। भाजपा के लिए यह जीत उल्लेखनीय रही, क्योंकि पार्टी ने शहरी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपना परचम लहराया।

प्रधानमंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने लिखा, "धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी जी, ये आपके नेतृत्व में विकास और विश्वास है जिसे आम आदमी समर्थन दे रहा है।" ■

प्रधानमंत्री मोदीजी ने दी जीत की बधाई

पहले फेस की तरह ही दूसरे फेस की जीत के बाद भी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पार्टी और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने ट्वीट किया, "ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे फेस में शानदार परिणाम, धन्यवाद महाराष्ट्र। बीजेपी में लगातार विश्वास कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है।"

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा

चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव कराने के लिए तिथियों की घोषणा कर दी है। हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर को मतदान होगा और 18 दिसंबर को परिणाम आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एके जोति हिमाचल प्रदेश चुनाव की घोषणा करते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से राज्य में आदर्श आचारसंहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही इस बार राज्य में सभी पोलिंग स्टेशनों पर VVPAT का इस्तेमाल होगा। देश में हिमाचल ऐसा पहला राज्य होगा, जहां सभी पोलिंग स्टेशन पर वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल (VVPAT) मशीन का इस्तेमाल होगा।

विदित हो कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 36 सीटें और भाजपा ने 26 सीटें जीती थीं। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने सभी 68 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रो. प्रेम कुमार धूमल को सुजानपुर सीट से टिकट दिया गया है, वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह ऊना से चुनाव लड़ेंगे। ■

पहला अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 17 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस पर नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किया। अब तक के इस पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) की स्थापना अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की तर्ज पर की गई है। आयुष मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संस्थान के रूप में एआईआईए आयुर्वेद की पारंपरिक बुद्धिमत्ता और आधुनिक नैदानिक उपकरण एवं प्रौद्योगिकी के बीच समन्वय स्थापित करेगा। केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री श्रीपद नाईक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर धनवंतरि जयंती मनाने के लिए उपस्थित जन समूह को बधाई दी। उन्होंने आयुष मंत्रालय को अखिल भारतीय आयुर्वेद की स्थापना के लिए सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता, जब तक वह अपने इतिहास और विरासत का सम्मान नहीं करता, उन्हें संजोकर नहीं रखता। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र अपनी विरासत को पीछे छोड़ देते हैं, वे अपनी पहचान भी खो बैठते हैं।

उन्होंने कहा कि जब भारत स्वतंत्र नहीं था, तब उसके ज्ञान और योग तथा आयुर्वेद जैसी इसकी परंपराओं का सम्मान नहीं किया जाता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के प्रत्येक जिले में एक आयुर्वेद अस्पताल की स्थापना करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षों में 65 से अधिक आयुष अस्पतालों का निर्माण किया गया है।

अपने स्वागत भाषण में श्री श्रीपद येस्सो नाईक ने घोषणा की कि निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ सरकार अगले पांच वर्षों के दौरान आयुर्वेद सुविधाओं में तीन गुना बढ़ोत्तरी के लिए प्रयास करेगी। मंत्री महोदय ने कहा कि भारत 2022 में अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनायेगा। इस अवसर पर हमारी कोशिश अगले पांच वर्षों में आयुर्वेद सुविधाओं में तीन गुना बढ़ोत्तरी करने की है।

श्री नाईक ने यह भी कहा कि इस लक्ष्य को अर्जित करने के लिए भारी मात्रा में निवेश करने की जरूरत है। इसलिए सरकार निजी क्षेत्र को भी आयुर्वेद के क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने 'आयुष्मान भारत' के स्वप्न को पूरा करने के लिए स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत–स्वस्थ भारत एवं स्टार्ट अप इंडिया जैसी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए चिकित्सकों, छात्रों एवं आयुर्वेद का अनुसरण करने वालों से अपील की।

उन्होंने उपस्थित जन समूह को उनके मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद एवं चिकित्सा की अन्य वैकिल्पक प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए उठाये गये कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों के दौरान आयुर्वेद में लोगों की दिलचस्पी और विश्वास कई गुना बढ़ा है। निजी क्षेत्र में भी आयुर्वेद अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है। मंत्रालय ने इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति में दवाओं और उपचारों को मानक

बनाने के लिए एक 'आयुर्वेद मानक दिशा निर्देश' का प्रकाशन किया है। भारतीय चिकित्सा फार्माकोपिया आयोग दवाओं के मानकीकरण के लिए कार्य कर रहा है।

श्री नाईक ने कहा कि विश्व भर में चिकित्सा की भारतीय प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने के लिए, मंत्रालय ने 29 देशों में आयुष सूचना प्रकोष्ठों की स्थापना की है। कई देशों में आयुर्वेद पीठों की भी स्थापना की गई है। मंत्रालय ने आयुर्वेद एवं योग के विकास के लिए अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

इस अवसर पर श्री नरेन्द्र मोदी ने 'आयुर्वेदिक मानक उपचार दिशा निर्देश' का विमोचन किया। आयुष मंत्रालय द्वारा इन दिशा निर्देशों को तैयार किया गया है। उन्होंने पुणे के राम मणि अयंगर स्मारक योग्य संस्थान, जिसकी घोषणा इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर की गई थी, को योग पुरस्कार प्रदान किये।

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए) की स्थापना 157 करोड़ रुपये के बजट के साथ 10.015 एकड के कुल परिसर क्षेत्र में की गई है। इसमें एक एनएबीएच प्रत्यायित अस्पताल एवं एक एकेडमिक ब्लॉक है। बाहर से आने वाले रोगियों को एआईआईए के अस्पताल ब्लॉक में सेवाएं प्रदान की जाती हैं और निशुल्क दवाएं दी जाती हैं।

वर्तमान में अस्पताल के ब्लॉक में चल रहे नैदानिक विशेषताओं में न्यूरोलॉजिकल एंड डिगेनेरेटिव डिसीज केयर यूनिट, रुमेटोलॉजी और मस्कुलोस्केलेटल केयर यूनिट, मधुमेह और मेटाबोलिक/एलर्जी संबंधी विकारों की देखभाल इकाई, योग, पंचकर्म क्लिनिक, क्रिया कल्प, मधुमेह रेटिनोपैथी क्लिनिक, क्षार एवं अनुशास्त्र कर्म और बांझपन क्लिनिक शामिल हैं। इसमें रोग विज्ञान, जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान और रेडियोलॉजी प्रयोगशालाओं/निदान सुविधाएं शामिल हैं। इनडोर रोगी विभाग में 200 बिस्तरों के लिए प्रावधान है। ■

थोक मूल्य सूचकांक गिरकर 2.60 प्रतिशत हुआ

मासिक थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर सितंबर, 2017 के दौरान (सितंबर, 2016 की तुलना में) 2.60 प्रतिशत (अनंतिम) रही, जबकि इससे पिछले महीने यह 3.24 प्रतिशत (अनंतिम) थी। पिछले वर्ष के इसी महीने में यह 1.36 प्रतिशत रही थी। वित्त वर्ष में अब तक क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति दर 0.97 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति दर 3.44 प्रतिशत थी। 'खाद्य उत्पाद' समूह का सूचकांक पिछले महीने के 150.8 अंक (अनंतिम) से 4 प्रतिशत घटकर 144.8 अंक (अनंतिम) रह गया। ऐसा फल एवं सब्जियों (15%), पान के पत्ते (6%), रागी (4%), बाजरा (3%), सूअर का मांस, मक्का एवं चाय (प्रत्येक 2%) और पोल्ट्री चिकन (1%) के दाम घटने के कारण संभव हुआ। वहीं, दूसरी ओर चना (10%), अरहर (3%), मसूर, उड़द एवं अंतर्देशीय मछली (प्रत्येक 2%), ज्वार, अंडे, जौ, चटनी व मसाले और मटर/चावली (प्रत्येक 1%) के दाम बढ़ गए।

'गैर-खाद्य पदार्थ' समूह का सूचकांक पिछले महीने के 120.6 अंक (अनंतिम) से 0.2 प्रतिशत घटकर 120.3 अंक (अनंतिम) रह गया। ऐसा पुष्प कृषि (10%), मूंगफली के बीज (5%), कच्ची कपास (3%) और अलसी (1%) के दाम घटने के कारण संभव हुआ। वहीं, दूसरी ओर कोपरा (नारियल) (12%), कच्चे रेशम (10%), सूरजमुखी एवं ग्वार बीज (प्रत्येक 4%), कच्चे जूट, तिल के बीज एवं कच्चे रबर (प्रत्येक 3%), कच्चे ऊन एवं सोयाबीन (प्रत्येक 2%) और अरंडी के बीज, खाल (कच्ची), सरसों के बीज, मेस्ता, कॉयर फाइबर एवं कुसुम (कार्डी बीज) (प्रत्येक 1%) के दाम बढ़ गए।

'खनिज' समूह का सूचकांक पिछले महीने के 118.2 अंक (अनंतिम) से 1.1 प्रतिशत बढ़कर 119.5 अंक (अनंतिम) हो गया। ऐसा तांबा सांद्र (6%), मैंगनीज अयस्क (2%) और चूना पत्थर (1%) के दाम बढ़ने के कारण हुआ। वहीं, दूसरी ओर क्रोमाइट (24%), लौह अयस्क (4%), जस्ता सांद्र एवं फॉस्फोराइट (प्रत्येक 2%) और सीसा सांद्र या कन्सन्ट्रेट (1%) की कीमतें घट गईं। ■

जन धन खातों का असर: ग्रामीण इलाकों में ज्यादा हुई बचत

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना में से एक जनधन योजना का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जनधन खाता खोलने से ग्रामीण इलाकों में न केवल महंगाई कम हुई है, बल्कि लोगों के पैसे भी बचे हैं। साथ ही शराब और तंबाकू जैसी चीजों की बिक्री में कमी आई है।

रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जिन इलाकों में खाते बड़ी संख्या में खोले गए हैं, उनमें शराब और तंबाकू जैसी चीजों की बिक्री में कमी आई है। रिपोर्ट में खुदरा मुद्रास्फीति के डेटा का हवाला देते हुए बताया गया है कि जिन राज्यों में ग्रामीण इलाकों में 50 प्रतिशत से ज्यादा जनधन खाते हैं, उन राज्यों में मुद्रास्फीति पर सकारात्मक असर पड़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे ग्रामीण इलाकों में मुद्रास्फीति भी धीमी हो सकती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों में लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी खर्च बढ़ाया है। गौरतलब है कि जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2014 किया गया था, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है। ■

69 लाख से भी अधिक ग्राहक अटल पेंशन योजना में शामिल

इस समय अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में 2690 करोड़ रुपये के अंशदान के साथ 69 लाख से भी ज्यादा ग्राहक हैं। एपीवाई ने लक्षित ग्राहकों को अपने दायरे में लाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। गौरतलब है कि अटल पेंशन योजना वित्तीय समावेश और वित्तीय सुरक्षा के तहत भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। साथ ही भारत में पेंशन कवरेज लगभग 12 प्रतिशत है।

56,226 जल संचयन संरचनाएं और 1,13,976 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि वर्ष 2015-16 (शुभारम्भ) में सूखा निरोधन, प्रसार कार्य एवं जिला सिंचाई योजना बनाने हेतु 555.5 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसके अंतर्गत 175 करोड़ रुपये मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण हेतु पक्के निर्माण कार्यों में सामग्री घटक को पूरित करने एवं 259 करोड़ रुपये देश के 219 बारंबार सूखा प्रभावित जिलों में तथा केन्द्रीय भू-जल बोर्ड द्वारा चिन्हित अति दोहित 1071 ब्लॉकों में भूजल पुनर्भरण (रिचार्ज), सूखा शमन तथा सूक्ष्म जल भंडारण सृजन के लिए राज्यों को जारी किए गए। वर्ष 2016-17 में सूखा निरोधन उपायों के लिए 520.90 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को जारी की गई। अब तक 56,226 जल संचयन संरचनाएं और 1,13,976 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई। 675 जिला सिंचाई योजनाएं तैयार की गई हैं। यह बात उन्होंने 14 अक्टूबर को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित भारत जल सप्ताह-2017 के समापन सत्र में कही।

उन्होंने जानकारी दी कि कृषि मंत्रालय को प्रति बूंद अधिक फसल नामक योजना के क्रियान्यवन की जिम्मेदारी दी गई है। 'प्रति बूंद अधिक फसल' घटक के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्त वर्ष 2011-14 के दौरान राज्यों को कुल 3699.45 करोड़ रुपये जारी किए गए थे और सूक्ष्म सिंचाई के अधीन 16.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाया गया था। वहीं, वित्त वर्ष 2014-17 के दौरान राज्यों को कुल 4509 करोड़ रुपये जारी किए गए और सूक्ष्म सिंचाई के अधीन 18.38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाया गया है, जो कि अब तक का सर्वाधिक क्षेत्र है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को 'प्रति बूंद अधिक फसल' के लिए 1991.17 करोड़ रुपये जारी किए गए, जो वर्ष 2015-16 में जारी 1,556.73 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 28 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2015-16 में सूक्ष्म सिंचाई के अधीन 5.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाया गया था तथा वर्ष 2016-17 में 8.39 लाख हेक्टर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया, जो कि अब तक का सर्वाधिक क्षेत्र है। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017-18 के लिए 'प्रति बूंद अधिक फसल' के अंतर्गत 3400 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसके सापेक्ष सितम्बर, 2017 तक 1601.40 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। सूक्ष्म सिंचाई के तहत वर्ष 2017-18 में 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को इसमें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

पीएमकेएसवाई को कमान क्षेत्र विकास सहित दिसम्बर 2019 तक चरणबद्ध तरीके से 76.03 लाख हेक्टेयर की क्षमता के साथ 99 वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से

मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूखे की समस्या से स्थायी निजात पाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के मिशन मोड वाले क्रियान्वयन में तीन मंत्रालय सम्मिलित हैं जिसकी अगुवाई जल संसाधन मंत्रालय कर रहा हैं। पीएमकेएसवाई का उद्देश्य न केवल सुनिश्चित सिंचाई हेतु स्रोतों का सृजन करना है, बल्कि 'जल संचय' और 'जल सिंचन' के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर वर्षा जल का उपयोग करके संरक्षित सिंचाई का भी सृजन करना है।

कृषि मंत्री ने कहा कि भारत में विश्व की आबादी की 17 प्रतिशत जनसंख्या तथा 11.3 प्रतिशत पशुधन निवास करते हैं, जबकि अपने देश में विश्व का मात्र 4 प्रतिशत जल संसाधन उपलब्ध है। ऐसे में हमारे समक्ष इतनी बड़ी मानव तथा पशुधन आबादी को पानी की आपूर्ति करने की अभूतपूर्व चुनौती है।

उन्होंने कहा कि देश में कुल 200.8 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से मात्र 95.8 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित है जो कि कुल क्षेत्रफल का केवल 48 प्रतिशत है, अतः 52 फीसदी असिंचित कृषि भूमि में उन्नत कृषि अपनाने हेतु आवश्यक जल की आपूर्ति कराना भी चुनौतीपूर्ण होगा। समुचित जल प्रबंधन करके ही इस चुनौती का सामना करना संभव है। कृषि मंत्री ने कहा कि 2015-16 से 2019-20 के दौरान 50,000 करोड़ रुपये निवेश कर संपूर्ण सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला, जल संसाधन, वितरण नेटवर्क और खेत-स्तरीय अनुप्रयोग समाधान विकसित करके 'हर खेत को पानी' उपलब्ध कराया जाएगा। ■

पटरियों पर बैठने वाले विक्रेताओं की समस्याएं

पटरी वालों का क्या किया जाए? क्या हम मानवता के दृष्टिकोण से इसका विचार कर सकते हैं? आज अधिकारी इस नाते विचार करने को तैयार नहीं कि लोगों की जीविका का प्रबंध करना भी उनकी जिम्मेदारी है। वे दिल्ली के सौंदर्य का विचार कर सकते हैं, मोटर के रास्ते की चिंता कर सकते हैं और दुकानदारों और पटरी वालों में संघर्ष पैदा करके अपना मतलब भी पूरा कर सकते हैं, किंतु इन पटरी वालों को कहीं दूसरी जगह बैठने का प्रबंध करने के लिए तैयार नहीं।

| दीनदयाल उपाध्याय |

दिल्ली में पटरी पर बैठने वाले विक्रेताओं की समस्या विषम रूप धारण करती जा रही है। शायद जितने दुकानदार हैं, उनसे ज्यादा संख्या ऐसे लोगों की है, जो बिना किसी दुकान के खोमचों, ठेलों और रेहड़ियों के सहारे अपनी जीविका चलाते हैं। दिल्ली नगरपालिका के उपनियमों के अनुसार इन लोगों को पटरियों पर बैठकर बेचने की इजाज़त नहीं है। दिल्ली के अधिकारियों के सामने ट्रैफ़िक की भी समस्या है, क्योंकि इन पटरी वालों और खोमचों वालों के कारण सड़क पर इतनी भीड़ हो जाती है कि मोटर आदि का तो निकलना ही दुष्कर हो जाता है। फिर दुकानदारों की भी शिकायत है। सामने पटरी पर बैठे हुए व्यापारियों के कारण दुकानदारी में भी बाधा पहुंचती है। नगर के सौंदर्य का भी प्रश्न है। टूटे-फूटे ठेलों और गंदे खोमचों से राजधानी की सड़कों का सौंदर्य मारा जाता है। फलतः दिल्ली सरकार ने पटरी वालों के खिलाफ जोरदार मुहिम छेड़ दी है। नगर पालिका के उपनियमों के अतिरिक्त धारा 144 लगाकर चांदनी चौक में पटरी वालों का बैठना रोक दिया है। अन्य क्षेत्रों में भी धारा लागू करने की योजना है।

फलतः दिल्ली के लगभग 21 हज़ार परिवार आज जीवन और मृत्यु के बीच की घड़ियां गिन रहे हैं। उनकी आजीविका का साधन जाता रहा है। अगर चोरी-छिपे कहीं पटरी पर बैठे कि पुलिस आ धमकती है। दो-चार आने देकर क़ानून के शिकंजे से बचा जाता है। अगर कोई टेढ़ा सा सिपाही आ गया तो वह गाली-गुफ्ता तथा मार-पीट के साथ उसके खोमचे को भी फेंक देता है। शाहदरा अड्डे पर कुछ आम बेचने वालों से पुलिस के सिपाही ने दो-दो आने के आम लिए। थोड़ी देर में सादा लिबास में एक इंस्पेक्टर साहब आए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के। उन्होंने आंखों से देखा था पुलिस के सिपाही को घूस लेते। फल वालों से मारपीट कर कबूल कराया कि उन्होंने सिपाही को दो-दो आने दिए, किंतु अंत में कुछ ले-देकर मामला रफा-दफा हो गया। बेचारे फल वालों की आत्मा इतनी दब गई कि उनसे पूछने पर वे सत्य बताने को भी तैयार नहीं और न कहीं इस घटना की शिकायत करने को राजी हैं।

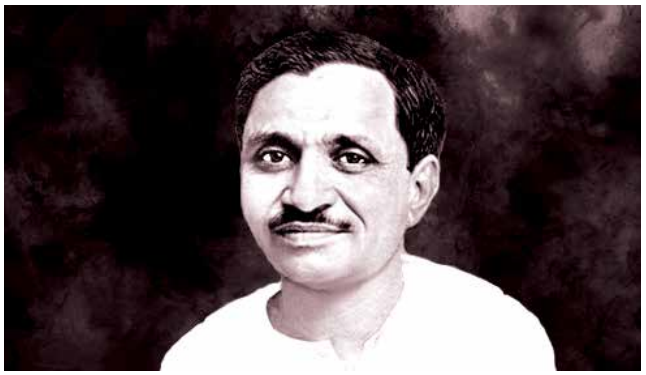

पहाड़गंज में एक पुलिस सिपाही ने एक घास बेचने वाली बुढ़िया की घास थोड़ी-थोडी करके संपूर्ण सड़क पर बिखेर दी। एक चाट वाले के खोमचे में फुटबॉल की तरह वह ठोकर मारी कि खोमचा दूर सड़क पर गिर पड़ा तथा चाट सड़क को चाटने लगी। इन घटनाओं के पीछे अधिकारियों की वह मनोवृत्ति है, जो नीरो की थी। डिग्री का अंतर हो सकता है, दृष्टिकोण का नहीं।

पटरी वालों का क्या किया जाए? क्या हम मानवता के दृष्टिकोण से इसका विचार कर सकते हैं? आज अधिकारी इस नाते विचार करने को तैयार नहीं कि लोगों की जीविका का प्रबंध करना भी उनकी जिम्मेदारी है। वे दिल्ली के सौंदर्य का विचार कर सकते हैं, मोटर के रास्ते की चिंता कर सकते हैं और दुकानदारों और पटरी वालों में संघर्ष पैदा करके अपना मतलब भी पूरा कर सकते हैं, किंतु इन पटरी वालों को कहीं दूसरी जगह बैठने का प्रबंध करने के लिए तैयार नहीं। आज भी क़ानून के विरुद्ध होते हुए चांदनी चौक में सड़क के दोनों ओर मोटरों की कतार-की-कतार खड़ी रहती है। उसे अधिकारी नहीं रोकते। इस क्षेत्र में मोटरों का आना भी रोका जा सकता है। अगर किसी को खरीद-फरोख्त के लिए आना है तो वह मोटर चांदनी चौक के बाहर छोड़कर पैदल आए।

दिल्ली का प्रश्न तो केवल उदाहरणस्वरूप है। आज देश में जिस प्रकार भूमिहीन किसानों की समस्या है, वैसे ही दुकानहीन व्यापारियों की भी बहुत बड़ी समस्या है। हमें उसका कोई हल ढूंढना होगा। हमारे

अधिकारियों को भी नगर का सुधार करने की धुन में केवल पश्चिम के नगरों का नहीं, अपितु भारत की आज की समस्या का भी विचार करना होगा। आज तो ऐसा लगता है कि अधिकारियों को लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का तो आधार दे दिया गया है, किंतु उनके ऊपर जिम्मेदारी कोई नहीं है। फिर बडे-बडे बंगलों में रहने वाले, मोटर में चलने वाले सभी प्रश्नों की ओर अपने ही चश्मे से देखते हैं। गरीबों की समस्या ही उनकी समझ में नहीं आती।

नेहरूजी की रूस यात्रा और गोवा मुक्ति का प्रश्न

नेहरूजी विदेश यात्रा के पश्चात् भारत आ गए हैं। देश के जन-जन ने उनका स्वागत किया है। उन्होंने भारत का संदेश रूस और पूर्वी यूरोप के उन क्षेत्रों तक पहुंचाया, जहां पिछले 35 वर्षो में दूसरे देश का आदमी तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। उनकी यश पताका दिग्दिगंत में फहराई, यह सब हमारे लिए गर्व की बात है। किंतु जब नेहरूजी वापस लौटकर आ गए हैं, हम पूछेंगे, 'आप हमारे लिए क्या लाए?' चीन और फारमोसा, जिनेवा और बड़ी शक्तियों की बातचीत इन सबकी तो चर्चा हुई, किंतु हमारे सामने तो प्रश्न है गोवा का। उसका क्या हुआ?

हम नेहरूजी को बताना चाहेंगे कि उनकी अनुपस्थिति में गोवा के प्रश्न को लेकर भारत में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ है। हमें नहीं मालूम कि विदेश में रहते हुए उन्हें देश की खबरें मिलती रहीं या नहीं। पर हम यह जानते हैं कि उन्होंने अपनी विदेश यात्रा में कहीं भी गोवा का जिक्र नहीं किया। पोप के साथ भी शायद इतनी ही वार्त्ता हुई है कि गोवा का प्रश्न राजनीतिक है। किंतु यह राजनीतिक प्रश्न हल कैसे होगा? इसका कोई विचार नहीं हुआ। हमें यह भी दुःख के साथ कहना पड़ता है कि नेहरूजी ने गोवा में हुए शहीद वीर अमीरचंद्र गुप्ता के संबंध में दो शब्द भी नहीं कहे। स्पष्ट है कि विदेशों में नेहरूजी देश को भूल गए। अतः देश में आकर वे घर की सुध लें। ऐसा न हो कि यहां भी वे विदेशों की रट लगाते रहें और उनके ही गुण गाते रहें।

क्या अनुसरण किया जाएगा?

गुड़गांव जिले का समाचार है कि वहां के जिला मजिस्ट्रेट ने अपने चौदह वर्षीय पुत्र के ऊपर अभियोग चलाने की आज्ञा दे दी है। पुत्र का अपराध है, प्रतिबंध होते हुए भी हवाई बंदूक से एक खरगोश की हत्या। मजिस्ट्रेट ने जिस न्याय-बुद्धि का परिचय दिया है, वह स्तुत्य है। क्या ही अच्छा हो, यदि हमारे सभी अधिकारी इस मनोवृत्ति का परिचय दें। इसके प्रतिकूल हमें ज्ञात है कि लाखों का घोटाला करने वाले व्यक्तियों की कांग्रेस शासन ने पुनः बढ़ोतरी की है। इंग्लैंड में जीप का सुविख्यात घोटला होने के पश्चात् भी श्री कृष्ण मेनन आज नेहरूजी के कृपापात्र होने के कारण सब प्रकार की जांच और अदालती कार्रवाई से बचाकर अधिकाधिक जिम्मेदारी के पदों पर लाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ऊपर के लोगों को ठीक करने के लिए नीचे से ही आदर्श उपस्थित करना पड़ेगा। यह जनतंत्र जो है। ■

- पांचजन्य, जुलाई 18, 1955

5.98 लाख एकल परिवारों के शौचालय बनाए गए

राज्य सरकारों तथा अन्य विभागों के साथ साझेदारी में ग्रामीण विकास विभाग ने 1 से 15 अक्तूबर, 2017 तक ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। 02 अक्तूबर को देश के लगभग सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने इस अवधि के दौरान 11 अक्तूबर, 2017 को मॉनीटरिंग पैनल एवं ग्राम संवाद ऐप लॉन्च किया। दिशा मॉनीटरिंग पोर्टल सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्रों में केंद्रीय रूप से प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का जायजा लेने में सक्षम बनाएगा। ग्राम संवाद मोबाइल ऐप नागरिकों को पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा उनके कार्यान्वयन के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।

स्वच्छ ग्राम पोर्टल पर दर्ज सूचनाओं के अनुसार इस अवधि के दौरान गांवों में 4.75 लाख स्वच्छता अभियान आरंभ किए गए। 38,283 गांवों को खुले में शौच से मुक्ति घोषित किया गया। 5.98 लाख एकल परिवारों के शौचालय बनाए गए और सभी ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पहल शुरू की गई। युवाओं के बीच कौशल विकास पर जोर दिया गया तथा कौशल प्रशिक्षण के लिए कौशल पंजी ऐप के जरिए मांग दर्ज करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कुल 1,404 कौशल रथ आरंभ किए गए।

इस अवधि में आयोजित रोजगार मेलों के दौरान कुल 1.35 लाख युवाओं को रोजगार दिलाए गए। इस अवधि के दौरान आयोजित समारोहों के 4 लाख से अधिक चित्र पहले ही स्वच्छ ग्राम पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। पंचायत कार्यालयों में सार्वजनिक उत्तरादायित्व का प्रदर्शन किया गया तथा लाभार्थियों की सूची के संपूर्ण खुलासे एवं निष्पादित किए जा रहे कार्यों के पूर्ण विवरण वहां उपलब्ध कराए गए हैं।

इस अवधि के दौरान पीएमएवाई (ग्रामीण) के बड़े पैमाने पर गृह प्रवेश तथा नए मकानों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किए गए। महिला स्व-सहायता समूहों में से लेखा परीक्षकों के चयन भी 92 हजार ग्राम पंचायतों में किए गए जहां दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यरत है। ■

'राजनीति के अजातशत्रु' कैलाशपति मिश्र

(5 अक्टूबर 1923 – 3 नवंबर 2012)

भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक श्री कैलाशपति मिश्र को बिहार भाजपा का 'भीष्म पितामह' कहा जाता है। श्री मिश्र का जन्म बक्सर जिले में दुधारचक गांव में 5 अक्तूबर, 1923 को हुआ था। पंडित हजारी मिश्र के अत्यंत साधारण व अभावग्रस्त परिवार में जन्म लेने के बावजूद बाल्यकाल से ही वे स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी हो गए। 1942 के 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' आंदोलन में 10वीं के छात्र रहते हुए जेल गए। 1945 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्पर्क में आए, तो फिर अपने राष्ट्र और समाज की सेवा ही उनका ध्येय बन गया। आजीवन अविवाहित रहकर अपने समाज की सेवा का जो संकल्प 1945 में उन्होंने लिया, उसे अंत तक निभाया।

संघ प्रचारक के रूप में आरा से सामाजिक जीवन प्रारंभ किया, 1947 से 52 तक पटना में प्रचारक रहे, 1952 से 57 तक पूर्णिया के जिला प्रचारक रहे, फिर संघ के निर्देश पर ही जनसंघ में गए। 1959 में जनसंघ के प्रदेश संगठन मंत्री का दायित्व मिला तो आपातकाल के बाद चुनावी राजनीति में उतरने के निर्देश का भी पालन किया। विक्रम विधानसभा से चुनाव जीत कर कर्पूरी ठाकुर की सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। 1980 में जनसंघ के नए रूप में सामने आयी भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के वे पहले प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत हुए, फिर 1983 से 1987 तक निर्वाचित अध्यक्ष रहे। इस बीच 1984 से 1990 तक राज्यसभा के भी सदस्य रहे। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ ही अनेक राज्यों के संगठन मंत्री का दायित्व भी उन्होंने बखूबी निभाया। 7 मई, 2003 से 7 जुलाई, 2004 तक वे गुजरात के राज्यपाल पद पर भी आसीन रहे। इसी दौरान 4 माह के लिए राजस्थान के राज्यपाल का कार्यभार भी उन पर था। इतनी सक्रिय, उच्चस्तरीय व सत्ता के इर्द-गिर्द घूमती राजनीतिक यात्रा में भी वे कभी डिगे नहीं, विचलित नहीं हुए।

50 वर्ष से अधिक लम्बी चली उनकी राजनीतिक जीवन की यात्रा में न उन पर कोई आरोप लगा और न ही वे किसी विवाद का अंग बने। राजनीति की दलदल में कमल के समान अहंकार, बुराई, द्वेष, लोभ-लालच आदि सामान्य दोषों से भी अछूते रहने वाले कैलाशपति अपनी इन्हीं विशिष्टताओं के कारण भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के लिए आज भी आदर्श एवं प्रेरणास्रोत हैं।

श्री कैलाशपति मिश्र एक साहित्यकार भी थे। उनकी लिखी पुस्तकों में 'पथ के संस्मरण' (आत्मकथा) और 'चेतना के स्वर' (कविता संग्रह) प्रमुख हैं। इनकी मृत्यु 3 नवंबर 2012 को पटना में हुई। ■

राजनैतिक सक्रियता

- 1942 के आंदोलन में सक्रिय भागीदारी (10 वीं का छात्र रहते जेल गए)
- 1945: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े (संघ परिवार को समर्पित किया जीवन, आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प)
- 1945-46: आरा के प्रचारक
- 1959: प्रदेश संगठन मंत्री
- 1977-80: विक्रम विधानसभा क्षेत्र से विधायक
- 1980: भाजपा के प्रथम प्रदेश (बिहार) अध्यक्ष
- 1983-87: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
- 1984-90: राज्यसभा सदस्य
- 1988-93: भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री
- 1993-95: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
- 1995-2003: भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
- राष्ट्रीय मंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व अंडमान निकोबार के संगठन मंत्री।
- 7 मई 2003 से 7 जुलाई 2004: गुजरात के राज्यपाल (इसी दौरान चार महीने के लिए राजस्थान के भी राज्यपाल)

सरल जीएसटी - देश के लिए दीपावली का उपहार

जीएसटी भारत में होने वाले व्यापार एवं कारोबार की प्रक्रिया को पूर्ण रुप से बदल रहा है। इसके कारण कीमतों में कमी आएगी, सरकार के राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी और जीएसटी नेटवर्क के एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से संचालित होने के कारण एक सरल व्यवस्था का निर्माण होगा। जीएसटी के अतंर्गत लगभग 13 केन्द्रीय और राज्य करों को सम्मिलित करके एक कर व्यवस्था लागू की गई है। हमारा उद्देश्य भारत में एक पारदर्शी, सुचारु और सुसंगत कर प्रणाली लागू करना है।

गोपाल कृष्ण अग्रवाल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी गुड एवं सिम्पल टैक्स (जीएसटी) के कारण ही हमारे नागरिकों के हितों को सुनिश्चित किया जा सकता है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोत्तरी हो रही है। वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के 100 दिन सफलतापूर्वक हो गए हैं। 'एक बाजार, एक कर' भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जोकि भारतीय अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से बदल देगा। कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के बाजार प्रादेशिक क्षेत्र में विभाजित थे। इसके अतिरिक्त विनिर्माण क्षेत्र कई तरह के करों और व्यापार के लिए सुगम वातावरण की कमी के कारण मुसीबत में था। जटिल अप्रत्यक्ष कर, इंस्पेक्टर राज में रजिस्ट्रेशन रिटर्न आदि में होने वाला उत्पीड़न और व्यक्तिगत रूप से रिटर्न भरना, असेसमेन्ट आदि को लेकर पनपता हुआ भ्रष्टाचार जीएसटी के चलते अब बंद हो जाएगा। अप्रत्यक्ष प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाने के लिए जीएसटी नेटवर्क के माध्यम से इसे ऑनलाइन और स्वचालित किया गया है।

जीएसटी भारत में होने वाले व्यापार एवं कारोबार की प्रक्रिया को पूर्ण रुप से बदल रहा है। इसके कारण कीमतों में कमी आएगी, सरकार के राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी और जीएसटी नेटवर्क के एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से संचालित होने के कारण एक सरल व्यवस्था का निर्माण होगा। जीएसटी के अतंर्गत लगभग 13 केन्द्रीय और राज्य करों को सम्मिलित करके एक कर व्यवस्था लागू की गई है। हमारा उद्देश्य भारत में एक पारदर्शी, सुचारु और सुसंगत कर प्रणाली लागू करना है।

पूर्ण क्रियान्वयन के बाद जीएसटी नेटवर्क को दिसंबर 2017 तक लागू किया जा सकेगा। यदि एक बार प्रारंभिक लेनदेन चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन जीएसटी सिस्टम में अपलोड हो जाएंगें, तो बाकी सूचनाएं स्वचालित रूप से रिर्टन एवं असेसमेन्ट के लिए प्रेषित हो जाएंगी। टैक्स कर्मियों के हस्तक्षेप के कारण पंजीकरण, मूल्यांकन और रिटर्न आदि में होने वाली परेशानी से व्यापारी स्वंय मुक्त हो जाएगा।

विमुद्रीकरण ने लोगों को अपने व्यापार को बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से करने के लिए प्रोत्साहित किया है। जिसके कारण ऑडिट ट्रैल की व्यवस्था की स्थापना हुई है। यह जीएसटी के सफल कार्यान्वयन के लिए पूर्ववर्ती आवश्यक है। एक बार जीएसटी का पूर्ण लाभ, जैसेकि इनपुट टैक्स क्रेडिट(आईटीसी) और टैक्स के कैस्केडिंग प्रभाव से मुक्त अधिकतम रिटेल प्राइस (एमआरपी) हो जाएगा, तो उपभोक्ता की कीमतें नीचे आ जाएंगी। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ संकेत दिए हैं कि बेहतर कर अनुपालन के बाद ही सरकार अप्रत्यक्ष करों की दर को कम कर सकती है, और अवश्य करेगी एसे संकेत भी मिल रहे है।

जीएसटी के कार्यान्वयन को लेकर कुछ मुद्दों पर आलोचनाएं हुई हैं। हमें सोशल मीडिया के द्वारा फैलाई जा रही कई गलत सूचनाओं से सावधान रहना चाहिए। कई लोग सोशल मीडिया में जीएसटी के 65,000 करोड़ रुपये के रिफंड की मांग बता रहें हैं, यह आंकड़ा सरासर गलत है। इस प्रकार की टैक्स क्रेडिट की मांग अन्तर्राज्यीय

जीएसटी आंकड़े के गलत आंकलन पर आधारित हैं।

वर्तमान सरकार देश की अभी तक की सबसे सक्रिय सरकार है। हमने कभी भी नकारात्मक रवैया नहीं अपनाया है। प्रधानमंत्री हमेशा सुझावों को सुनने और स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने भारतीय सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के समारोह में जीएसटी कानूनों में बदलाव के साफ संकेत दिए थे।

जीएसटी परिषद् की 22वी बैठक में लोगों के सक्रिय सुझाओं को सुनिश्चित करते हुए बड़े बदलाव किए गए। इन परिवर्तनों से सरल व्यापारिक प्रकिया को बढ़ावा मिलेगा, जोकि छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए नई संभावनाओं को जन्म देगा। इन परिवर्तनों से निर्यातकों को भी महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। परिषद् ने उद्योग में सामान्य रूप से प्रयोग होने वाली 27 विभिन्न वस्तुओं जैसे धागे, डीजल इंजन पंपों आदि के जीएसटी दरों को संशोधित कर दिया है। यह कदम निश्चित रूप से समाज के गरीब वर्गों और किसानों को सशक्त बनाएगा।

कम्पोजिट स्कीम के तहत 75 लाख की सीमा को एक करोड़ तक बढ़ाना छोटे व्यापारियों को राहत देगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) को स्थगित कर दिया गया है और 1 अप्रैल 2018 से लागू किया जाएगा। यहां तक कि माल परिवहन एजेंसियों द्वारा अपंजीकृत व्यापारियों के मालवाहन भी जीएसटी में छूट दी गई है, जोकि परिवहन क्षेत्र की एक प्रमुख मांग है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) पर उद्योगों की मांग पर सहमति के तहत इसको 31 मार्च 2018 तक टाल दिया गया है। 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाल करदाताओं को माल की बिक्री के समय मिलने वाली अग्रिम राशि पर जीएसटी का भुगतान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सालाना 20 लाख से कम के टर्नओवर वाले छोटे सेवाओं को प्रदाताओं की छूट के दायरे में, भले ही अन्तर्राज्यीय कर योग्य सेवाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने एक अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर कहा था कि 'जीएसटी के तहत सरकार कई आकर्षक योजनाएं लेकर आई है, ताकि भारत में जो गैर कर अनुपालन है उसे रोका जा सके। कुछ लोगों के लिए जीएसटी में समस्या यह है कि गैर-अनुपालन मुश्किल हो जाएगा। आंकड़ें दिखाते हैं कि कर का लगभग 95 प्रतिशत केवल 4,00,000 असेसियों के द्वारा ही भुगतान किया जाता है। इस कर के आधार को निचले स्तर पर विस्तार करने की आवश्यकता है। नोटबंदी और जीएसटी यही काम कर रहे हैं।'

श्री अरुण जेटली जी ने कहा कि 'जीएसटी के लागू होने की प्रक्रिया को पटरी से उतारने की विपक्ष के नेताओं की कोशिशों के बावजूद भारत में जीएसटी आराम से लागू हो गई।' उन्होंने आगे कहा कि 'जीएसटी को असफल करने के लिए राजनैतिक समूहों ने काफी प्रयास किये, लेकिन मुझे खुशी है कि उनकी अपनी राज्य सरकारें भी उनकी नहीं सुन रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जीएसटी से आने वाली राशि में से 80 प्रतिशत उन्हें ही मिलने वाली है। राज्यों को प्रतिस्पर्धी संघवाद के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है और सरकार व्यापारिक सरलता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग कर रही है।

जीएसटी परिषद् भारत की पहली वास्तविक संघीय संस्था है जो हर महीने मिलती है, मासिक रुप से स्थिति की समीक्षा करती है और निर्णय लेती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण एक ऐसे समय पर हो रहा है, जब अन्य अर्थव्यवस्थाएं ज्यादा से ज्यादा संरक्षणवादी बन रही हैं। पिछले तीन वर्षों से सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की श्रृंखला के चलते भारत अब व्यापार करने के लिए एक बेहतर एवं सरल स्थान है। हमारा विश्वास है कि जीएसटी जैसे बड़े ढांचागत सुधारों के कारण भारत अब बड़े निर्णय लेने और उन्हें विस्तृत स्तर पर लागू करने में सक्षम हो गया है। ■

(लेखक भाजपा के आर्थिक मामलों के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं)

'जीएसटी लागू करने जैसे सुधार के कदमों से अर्थव्यवस्था सुधरेगी'

उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि जीएसटी लागू करने जैसे सुधार के कदमों से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। उपराष्ट्रपति 17 अक्टूबर को चेन्नई में आंध्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 90वें स्थापना समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि विश्व टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्रांति के कारण तेजी से बदल रहा है। परिवर्तन के साथ नहीं चलने वाला कोई भी देश पिछड़ जाएगा। भारत प्रमुख आर्थिक शक्ति बनने की ओर बढ़ गया है और देश के विकास में तेजी लाने में निजी क्षेत्र बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि विकास में तेजी लाने के लिए हमें संरचना में सुधार करना होगा, संसाधन क्षमता बढ़ानी होगी और नवाचारी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करना होगा।

श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई सहित आर्थिक वृद्धि के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों से भारत तेजी से विकसित होगा। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित 'देश परिदृश्य' के अनुसार आर्थिक गतिविधि में स्थिरता आएगी और 2018 में जीडीपी में सात प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। श्री नायडू ने कहा कि रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020 तक विकास दर बढ़कर 7.4 प्रतिशत हो जाने की बात भी कही गई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख ने बताया है कि मंदी लघु अवधि की है और हम भारतीय अर्थव्यवस्था के ठोस रास्ते पर चलने का भविष्य देखते हैं।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी देश और समाज की प्रगति के प्रमुख मानकों में महिला सशक्तिकरण एक है। मुझे इस बात की खुशी है कि श्रीमती इंदिरा दत्त के नेतृत्व में आंध्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा महिला बिजनेस फोरम स्थापित किया गया है, ताकि महिला विद्यार्थियों और कर्मचारियों को उद्यमी बनने का प्रशिक्षण दिया जा सके। ■

केरल में साम्यवादी दमन अंत की ओर

जयकृष्ण गौड़

कम्युनिस्टों की शासन व्यवस्था में न तो विरोधी विचारों को बर्दाश्त किया जाता है और न विरोध को। चाहे रूस की क्रांति हो या माओवादी क्रांति हो, इनके द्वारा खूनी तानाशाही को ही जन्म दिया गया। मार्क्सवाद के विचारों के आधार पर सर्वहारा वर्ग की न सरकार बनी और न कहीं वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी। जिस सोवियत संघ को साम्यवादी व्यवस्था का मॉडल बताया जाता था, वहीं स्टालिन जैसा तानाशाह पैदा हुआ, जिसके अत्याचार से सोवियत संघ की जनता त्राहि-त्राहि कर उठी।

जिस रोटी-कपड़ा-मकान के नारों से साम्यवादी विचार प्रभावी हुआ, वह रोटी- रोजी तो नहीं दे सका और लोगों को भिखारी की तरह रोटी की लाइन में खड़ा कर दिया। सोवियत संघ की जनता ने कम्युनिस्ट तानाशाही को उखाड़ फेंकने के साथ सोवियत संघ का भी अंत कर दिया। वहां कम्युनिस्टों से इतनी नफरत हुई कि लेनिन-स्टालिन की प्रतिमाओं को भी लोगों ने ध्वस्त कर दिया। चीन की माओवादी क्रांति से चीन में एकदलीय तानाशाही स्थापित है, मार्क्सवादी और माओवादी व्यवस्था ने ऐसी तानाशाही को जन्म दिया जिसमें न अभिव्यक्ति की आजादी है, न अन्य विचारों को बर्दाश्त किया जा सकता है, इन विचारों में लोकतंत्र का भी कोई स्थान नहीं है। चीन भी चाहे माओवादी मुखौटा लगा रखे, लेकिन वह भी खुली आर्थिक व्यवस्था को अपना कर ही प्रगति कर सका है। शक्ति के द्वारा दूसरे कमजोर देशों पर काबिज होता रहा है। चीन ने तिब्बत को हड़पा, अब भारत की सीमा में घुसपैठ करने की साजिश कर रहा है। साम्यवादी इतिहास के पन्नों में मनुष्य के खून के छींटे ही दिखाई देते है। भारत के कम्युनिस्टों के इतिहास में गद्दारी का चरित्र भी है। आजादी के संघर्ष में कम्युनिस्टों ने देश भक्तों की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। अब 1962 में चीन ने भारत की दोस्ती का खून करते हुए अचानक हमला किया, तो इन मार्क्सवादियों ने एजेन्ट की तरह चीन की पैरवी की। कुल मिलाकर साम्यवादी विचारों से बनी शासन व्यवस्था से तानाशाही, अत्याचार, विरोधी विचारों का दमन, विरोधियों को कुचलना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस करना ही रहा है। जब पं. बंगाल में 35 वर्षों तक साम्यवादी शासन रहा, तो वहां भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति रही। केरल, त्रिपुरा भी साम्यवादी सरकारों की त्रासदी भुगत रहे है। दुनिया ने साम्यवादी विचारों को नकार दिया है। भारत में भी इनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है, अब सीताराम येचुरी, करात आदि नेताओं की आवाज को मीडिया भी महत्व नहीं देता। कहावत है कि मरता-क्या न करता, यही कारण है साम्यवादी विचारों को नकारे जाने से कामरेड तिलमिलाये हुए हैं।

केरल की कम्युनिस्ट विजयन सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रही है, बताया जाता है कि करीब दो सौ संघ-भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या इस वर्ष हुई है। इस दमन के बाद भी राष्ट्रवादी विचारों को केरल की जनता आत्मसात कर रही है। छोटा राज्य होने के बाद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य और विचार वहां के सुदूर गांवों तक पहुंच गया है। साम्यवादी शासन व्यवस्था भी लड़खड़ा रही है, केरल की जनता साम्यवादी गुलामी से मुक्त होना चाहती है। केरल के प्रथम मुख्यमंत्री मार्क्सवादी नेता एम.एस. नंबूदरीपाद हुए। अभी तक वहां बारह मुख्यमंत्रियों की सरकारें रही है। वहां कम्युनिस्ट, कांग्रेस मोर्चा की भी सरकारें बनीं। यहां मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस ने अपने गठजोड़ में शामिल किया। घोर मजहबी साम्प्रदायिकता को गले लगाने वाली कांग्रेस की राजनीति से सेकुलर शब्द को तिरोहित कर देना चाहिए। करीब तीन करोड़ 18 लाख की जनसंख्या वाला केरल अपनी सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। केरल में गणित और ज्योतिष का विकास आर्य भट्ट की रचना आर्यभटीय के आधार पर हुआ है। गणित का इतिहास यह मानता है कि कलन (केलक्यूलस) का अविष्कारक आई जेक न्यूटन और लेवनीज नहीं होते हुए केरल के गणित वैज्ञानिक है। पौराणिक कथा के आधार पर माना जाता है परशुराम ने अपना परशु (फरसा) समुद्र में फेंका, उसके कारण उस आकार की भूमि समुद्र से बाहर निकली, जिसे केरल कहा गया। केरल की संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है, यह वहीं हिन्दू संस्कृति है जिसके प्रवाह को आज तक कोई बाधित नहीं कर सका। मलयालम भाषा की उत्पत्ति भी संस्कृत से हुई है। 'राम चरितम' को मलयालम का आदि काव्य माना जाता है। रामकथा, कृष्ण भजनों की गूंज केरल के हर हिन्दू के घर में सुनाई देती है। साहित्य, संस्कृति और

गौरवशाली इतिहास के तहस नहस करने की साजिश कम्युनिस्टों ने की। मुस्लिम लीग के कारण केरल के कई मुस्लिम युवक आईएस के जिहादी आतंकवादी बनने सीरिया गए है। केरल को मिनी पाकिस्तान बनाने की साजिश चल रही है।

केरल की सांस्कृतिक ऊर्जा के कारण चाहे वहां कम्युनिस्टों का शासन हो, लेकिन सांस्कृतिक अवधारणा का प्रभाव वहां के जनमन में है। राजनीतिक दृष्टि से भी केरल की जनता साम्यवादी विचारों को दफनाना चाहती है, वहां भी राष्ट्रीय विचारों की विजय पताका फहराने के लिए जनता उत्सुक है, ये विचार जितने प्रभावी होंगे, उतना ही कम्युनिस्ट सरकार का दमन बढ़ेगा। दमन का शासन अधिक समय तक नहीं रह सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक दमन का सामना करते हुए, बलिदान देते हुए अपने विचार और कार्य पर न केवल अडिग हैं, बल्कि केरल का हर व्यक्ति राष्ट्रवादी विचारों के साथ खड़ा दिखाई देता है।

विरोधी तत्वों के आतंक और हिंसा का सामना करने के लिए अब आम लोग भी आगे आ रहे है। यही कारण है कि भाजपा की जन रक्षा रैली में जन सैलाब उमड़ा। राजनीतिक पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कम्युनिस्टों के लालगढ़ में भाजपा प्रभावी दस्तक देने में भी सफल हो रही है। रैली में उमड़े जनसैलाब से केरल के राजनीतिक भविष्य का आंकलन होने लगा है। जन रक्षा रैली का नेतृत्व चाहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने किया हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिवराजसिंह आदि के नेतृत्व में जन सैलाब उमड़ा हो, यह तो लगता है कि पश्चिम बंगाल की तरह केरल की जनता भी कम्युनिस्ट शासन को उखाड़ फेंकना चाहती है। जिस तरह भगवान परशुराम ने अपने परशु से केरल की उत्पत्ति की, वहीं सांस्कृतिक परशु की शक्ति से साम्यवादी विचार केरल में भी पराजित हो चुके हैं। कोई भी विचार जनता के नकारे जाने के बाद किसी गुफा में छिपकर बच नहीं सकता। अब भारत में कम्युनिस्टों का अस्तित्व केवल केरल, त्रिपुरा में शेष है। पश्चिम बंगाल में तो अब कम्युनिस्ट तीसरे- चौथे

केरल की सांस्कृतिक ऊर्जा के कारण चाहे वहां कम्युनिस्टों का शासन हो, लेकिन सांस्कृतिक अवधारणा का प्रभाव वहां के जनमन में है। राजनीतिक दृष्टि से भी केरल की जनता साम्यवादी विचारों को दफनाना चाहती है, वहां भी राष्ट्रीय विचारों की विजय पताका फहराने के लिए जनता उत्सुक है।

नंबर पर सिमट गए है। जिन विचारों में लोकतंत्र नहीं हो, जो हिंसा में विश्वास करते हों, जिन विचारों में राष्ट्रीय सरोकार नहीं हों, ऐसे साम्यवादी विचारों की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, इन विचारों की भूमि से तानाशाह ही पैदा हुए हैं। ■

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

प्रधानमंत्री ने केदारनाथ का दौरा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 20 अक्टूबर को केदारनाथ का दौरा किया। उन्होंने केदारनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की और पांच आधारभूत संरचना और विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में मंदाकिनी नदी के किनारे दीवार और घाट का विकास, सरस्वती नदी के किनारे दीवार और घाट का विकास, केदारनाथ मंदिर तक सीधे पहुंचने के लिए मेन एप्रोच का निर्माण, शंकराचार्य कुटीर एवं शंकराचार्य संग्रहालय का विकास, केदारनाथ के पुरोहितों के लिए घरों का निर्माण शामिल हैं । प्रधानमंत्री को केदारपुरी के पुनर्निर्माण परियोजना के बारे में भी जानकारी दी गयी ।

केदारनाथ में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वह दीवाली के अगले दिन वहाँ पहुंचकर बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने बताया कि आज के दिन गुजरात में नव वर्ष की शुरुआत होती है, इस मौके पर उन्होंने पूरे विश्व के लोगों को शुभकामनाएं दीं। यह बताते हुए कि जन सेवा ही प्रभु सेवा है, प्रधानमंत्री ने 2022 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित करने का संकल्प लिया। 2022 में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होंगे । 2013 की प्राकृतिक आपदा को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने वह सब कुछ किया जो वह कर सकते थे। साथ ही उन्होंने इलाके के पुनर्निर्माण के लिए गुजरात से मदद का भी प्रस्ताव दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केदारनाथ में होने वाले कार्यों के जरिये कोई भी यह समझ सकता है कि एक आदर्श तीर्थ स्थल कैसा होना चाहिए...चाहे वह श्रद्धालुओं के लिए सुविधा की बात हो या पुरोहितों के कल्याण की बात हो। उन्होंने बताया कि केदारनाथ में पूरी होने वाली परियोजनाएं उच्च गुणवत्ता की होंगी...वे आधुनिक तो होंगी पर साथ ही साथ वे पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करेंगी और पर्यावरण को हानि न हो यह सुनिश्चित करेंगी। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हिमालय आध्यात्म, रोमांच पर्यटन और प्रकृति प्रेमी के लिए काफी कुछ दे सकता है। उन्होंने सभी को हिमालय आने के लिए आमंत्रित किया । इस मौके पर उत्तराखंड के राज्यपाल डा. के के पॉल और मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत भी उपस्थित रहे। ■

मजबूत है देश की अर्थव्यवस्था: नरेंद्र मोदी

द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के गोल्डन जुबली ईयर समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास के लिए और बड़े फैसले लेंगे, चुनावी फायदे के लिए देश का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते। श्री मोदी ने कहा कि देश के आर्थिक क्षेत्र को खोलने के बाद से लेकर अब तक जितना विदेशी निवेश भारत में हुआ है, उसकी तुलना अगर पिछले तीन वर्षों में हुए निवेश से करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारी सरकार जो रिफॉर्म कर रही है, उसका नतीजा क्या मिल रहा है। यहां प्रस्तुत है उनके संबोधन के मुख्य अंश का दूसरा और अंतिम भाग:

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर इसी तरह रेलवे सेक्टर की बात करें, तो पिछली सरकार के आखिरी तीन वर्षों में लगभग 1100 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण हुआ था। इस सरकार ने तीन वर्षों में 2100 किलोमीटर से ज्यादा तक पहुंच गए हम। यानी हमने लगभग दोगुनी गति से नई रेलवे लाइन बिछाई है। पिछली सरकार के आखिरी तीन सालों में 1300 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण हुआ, जबकि इस सरकार के तीन साल में 2600 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण हुआ है, यानी हमने दोगुनी रफ्तार में रेल लाइनों का दोहरीकरण करके दिखाया है।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के आखिरी के तीन वर्षों में लगभग 1 लाख 49 हजार करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया था। इस सरकार के तीन वर्षों में लगभग 2 लाख 64 हजार करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है। यानी ये भी 75 प्रतिशत से ज्यादा है।

श्री मोदी ने कहा कि अगर अब मैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूं- सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और उसके विकास की मैं चर्चा करूं- पिछली सरकार के आखिरी के तीन वर्षों में कुल 12 हजार मेगावॉट की रिन्यूएबल एनर्जी की नई क्षमता जोड़ी गई थी, अगर इस सरकार के तीन सालों की बात करें, तो 22 हजार मेगावॉट से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी की नई क्षमता को ग्रिड पावर से जोड़ा गया है। यानी यहां भी सरकार का परफॉरमेंस लगभग दोगुना अच्छा है। पिछली सरकार ने अपने आखिरी के तीन सालों में रिन्यूएबल एनर्जी पर 4 हजार करोड़ रुपया खर्च किया था। हमारी सरकार ने अपने तीन साल में इस सेक्टर पर 10600 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च किए हैं।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की तुलना में शिपिंग इंडस्ट्री में विकास की बात करें, तो जहां पहले जहां कार्गो हैंडलिंग की ग्रोथ निगेटिव थी, वहीं इस सरकार के तीन सालों में 11 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई है। देश के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े रेल-सड़क-बिजली जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों के साथ-साथ, सरकार सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने पर पूरा ध्यान दे रही है।

श्री मोदी ने कहा कि हमने सस्ते आवास के क्षेत्र में ऐसे-ऐसे नीतिगत निर्णय लिए हैं, वित्तीय सुधार किए हैं, जो इस क्षेत्र के लिए अभूतपूर्व हैं। पिछली सरकार ने अपने पहले के तीन वर्षों में सिर्फ 15 हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी, इस सरकार ने अपने पहले के तीन वर्षों में 1 लाख 53 हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है और ये वो प्रोजेक्ट हैं जो गरीबों को, मध्यम वर्ग को घर देने के हमारे कमिटमेंट की ताकत दिखाता है। देश में हो रहे इन चौतरफा विकास कार्यों के लिए अधिक पूंजी निवेश की भी आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा विदेशी पूंजी कैसे भारत आए, इस पर भी सरकार बल दे रही है।

श्री मोदी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ को याद होगा कि जब देश में इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म की चर्चा हुई थी तो अखबारों की हेडलाइन बनती थी- मैं पिछली सरकार की बात करता हूं- हेडलाइन बनती थी कि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा आर्थिक रिफॉर्म माना जाएगा। खैर पिछली सरकार नहीं कर पाई। वो सरकार चली गई, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म नहीं हुआ। बहुत अच्छे काम हैं वो हमारे लिए छोड़कर गए हैं।

श्री मोदी ने कहा कि ये रिफॉर्म हमने किया, इस सरकार में हुआ और पहले जो मानसिकता थी उससे काफी अच्छा किया और अधिक किया, लेकिन वो शल्य वृत्ति की समस्या है कि उनको ये रिफॉर्म नजर ही नहीं आया। जो कभी हैडलाइन हुआ करता था कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, होने के बाद शल्य वृत्ति रुकावट बन गई, क्योंकि ये पसंद इसलिए नहीं आता है ये रिफॉर्म उस दौर में नहीं हुआ। उनकी पसंद की सरकार ने नहीं किया। रिफॉर्म-रिफॉर्म के गीत गाने वालों को भी मैं बताना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में 21 क्षेत्रों में 87 छोटे-बड़े रिफॉर्म करने का काम इस सरकार ने करके दिखाया है। चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, चाहे डिफेन्स सेक्टर हो, चाहे फाइनेंसियल सर्विसेज का सेक्टर हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग का हो, जैसे कितने ही सेक्टरों में निवेश के नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं।

उन्होंने कहा कि देश के आर्थिक क्षेत्र को खोलने के बाद से लेकर अब तक जितना विदेशी निवेश भारत में हुआ है, उसकी तुलना अगर पिछले तीन वर्षों में हुए निवेश से करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारी सरकार जो रिफॉर्म कर रही है, उसका नतीजा क्या मिल रहा है। ये जो मैं आंकड़े बताने वाला हूं- आप इस क्षेत्र के हैं, आप इसी क्षेत्र में डूबे हुए लोग हैं, लेकिन अब मैं जो आंकड़े दे रहा हूं, मैं बिल्कुल बताता हूं, आप चौंक जाएंगे। 1992 के बाद उदारीकरण का कालखंड शुरू हुआ। अगर मैं उसी को एक आधार मानूं तो क्या स्थिति है। उसका हिसाब देखिए- उदारीकरण से ले करके 2014 तक, 2014 से 2017 तक क्या हुआ है- कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अब तक के कुल विदेशी पूंजी निवेश का 75 प्रतिशत सिर्फ इस तीन साल में आया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी अब तक के कुल विदेशी पूंजी निवेश का 69 प्रतिशत पिछले तीन वर्ष में आया है। माइनिंग सेक्टर में अब तक के कुल विदेशी पूंजी निवेश का 56 प्रतिशत, पिछले तीन साल में आया है। कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में भी अब तक के कुल विदेशी पूंजी निवेश का 53 प्रतिशत पिछले तीन वर्ष में आया है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में भी अब तक के कुल विदेशी पूंजी निवेश का 52 प्रतिशत, इसी सरकार ने तीन वर्षों में हासिल किया है। रिन्यूएबल एनर्जी, इस सेक्टर में भी अभी तक के कुल विदेशी पूंजी निवेश का 49 प्रतिशत, इसी सरकार के तीन साल में देश ने प्राप्त किया है।

श्री मोदी ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में अब तक के कुल विदेशी पूंजी निवेश का 45 प्रतिशत इन तीन साल में आया है और एक चौंकाने वाली बात बताता हूं। 1980 से हमारे यहां ऑटो-मोबिलाइजेशन में उदारीकरण की चर्चा रही है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जिसमें पहले से ही काफी विदेशी पूंजी निवेश हो चुका है, उस सेक्टर में भी, ये आपको हैरानी होगी सुन करके, उस सेक्टर में भी कुल विदेशी पूंजी निवेश का 44 प्रतिशत इसी तीन साल में आया है।

उन्होंने कहा कि भारत में FDI इनफ्लो का बढ़ना इस बात का सबूत है कि विदेशी निवेशक देश की अर्थव्यवस्था पर कितना भरोसा कर रहे हैं। एक सरकार ने विश्वास पैदा किया है। इसी का ये नतीजा है। नीतियों के कारण विश्वास पैदा हुआ है। नीति और रीति के कारण पैदा हुआ है और उससे भी ऊपर हमारी नीयत के कारण पैदा हुआ है। ये सारे निवेश देश के विकास की गति को तेज करने और जॉब क्रिएशन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इतने रोड बढ़ना, इतनी रेल बढ़ना, इतनी ये वृद्धि होना, क्या जॉब क्रिएशन नहीं होते हैं क्या। ऐसे ही हो गया होगा क्या? लेकिन अब शल्य वृत्ति चल रही है।

मेहनत से कमाए गए आपके एक-एक पैसे की कीमत ये सरकार भली-भांति समझती है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं और इसलिए सरकार की नीतियों और योजनाओं में इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो गरीबों और मध्यम वर्गों की जिंदगी तो आसान बनाएं हीं, उनके पैसों की बचत हो।

उन्होंने कहा कि मेहनत से कमाए गए आपके एक-एक पैसे की कीमत ये सरकार भली-भांति समझती है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं और इसलिए सरकार की नीतियों और योजनाओं में इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि वो गरीबों और मध्यम वर्गों की जिंदगी तो आसान बनाएं हीं, उनके पैसों की बचत हो।

उन्होंने कहा कि ये सरकार की लगातार कोशिश का ही नतीजा है,

कि पिछली सरकार के समय, अब ये भेद देखिए कि वहीं मध्यम वर्गीय परिवार, निम्न- वर्गीय परिवार का पैसा कितना बच रहा है। पिछली सरकार के समय जो एलईडी बल्ब था उसकी कीमत 350 रुपए थी, अब इसकी कीमत सरकार ने 'उजाला स्कीम' का बड़ा अभियान चलाया, साढ़े तीन सौ का एलईडी बल्ब 40-45 रुपये पर आ गया। अब मुझे बताइए जो एलईडी बल्ब खरीदने वाला मध्यम वर्गीय, निम्न-मध्यम वर्गीय, उसकी जेब में पैसा बचा कि नहीं बचा? उसको मदद हुई कि नहीं हुई? और अब समझ में नहीं आता है उस समय 350 रुपए क्यों थे? अब वो खोज का विषय है।

श्री मोदी ने कहा कि अब तक देश में 26 करोड़ से ज्यादा एलईडी बल्ब बांटे गए हैं। अगर एक बल्ब की कीमत में औसतन 250 रुपए की भी कमी मानें, तो देश के मध्यम वर्ग को इससे लगभग साढ़े 6 हजार करोड़ रुपयों की बचत हुई है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इतना ही नहीं, ये बल्ब हर घर में बिजली की खपत कम कर रहे हैं, तो इसमें बिजली का कंजम्पशन कम होता है और बिजली बिल कम कर रहे हैं। इससे भी देश के मध्यम वर्ग में सिर्फ एक साल में, ये एलईडी बल्ब लगाने वाले परिवारों में एक साल में देश में करीब-करीब 14 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा अनुमानित राशि की बचत हुई है। पहले मैंने बताया एलईडी बल्ब खरीदी में 6 हजार, बिजली कंजम्पशन में 14 हजार करोड़। 20 हजार करोड़ रुपये करीब-करीब बचना। ये अपने-आप में मध्यम वर्गीय परिवारों में कितनी ताकत देता है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने कोशिश की और उसकी वजह से जहां लोकल बॉडीज हैं, अपनी स्ट्रीट लाइट, लोकल बॉडीज की जो स्ट्रीट लाइट हैं, उसमें भी एलईडी बल्ब लग रहे हैं। काफी शहरों ने लगाए हैं। उन नगरपालिका, महानगर पालिकाओं को भी आर्थिक फायदा हो रहा है। अगर हम Tier-II सिटीज देखें, जिसका एक मोटा-मोटा मैं अंदाज करता हूं, तो करीब-करीब सालाना उनका बिजली बिल 10 से 15 करोड़ रुपये कम हुआ है। 10-15 करोड़ रुपये एक नगरपालिका में खर्चा कम होने का मतलब, उस नगर के अंदर सुविधाएं बढ़ाने के लिए उसके पास आर्थिक व्यवस्था पनपी है।

श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग को घर बनाने के लिए पहली बार- हमारे देश में मध्यम वर्ग को घर बनाने में ब्याज दर की कभी भी राहत नहीं दी गई। पहली बार ये सरकार है जिसने मध्यम वर्ग के लोगों को अपना घर बनाने के लिए ब्याज के अंदर मदद करने के लिए फैसला किया है। मध्यम वर्ग का बोझ कम करने, निम्न मध्यम वर्ग को अवसर प्रदान करने और गरीबों का सशक्तिकरण करने के लिए ये सरकार लगातार ठोस कदम उठाती रहती है। नीतियां बनानी होती हैं, और उसे समयबद्ध तरीके से लागू भी करना होता है और इस मकसद को पूरा करने के लिए हम हर कदम उठाते रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि मैं जानता हूं, राजनीति का स्वभाव मैं भलीभांति जानता हूं, समझता भी हूं कि रेवड़ी बांटने के बजाय- चुनाव आए रेवड़ी बांटो, लेकिन क्या रेवड़ी बांटने के बजाय भी देश को मजबूत करने के लिए कोई और रास्ता नहीं हो सकता है? क्या सिर्फ सत्ता और वोट की ही चिंता करेंगे? हमने वो रास्ता चुना है, कठिन है; लेकिन वो रास्ता चुना और और उसमें हम एम्पावरमेंट ऑफ़ पीपुल, उसको हम कर रहे हैं और उसके कारण मेरी आलोचना भी होती है, क्योंकि रेवड़ी बांटो तो जय-जयकार करने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। मेरी आलोचना भी होती है। बहुत आलोचना होती है, हितधारक तत्वों को काफी तकलीफ होती है। अगर मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसे भेजता हूं, तो कई जो भूतिया लोग, नकली लोग फायदा उठाते थे, अब उनके नाम कम हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि तब वो मोदी को पसंद कैसे करेगा जी? और इसलिए सामान्य मानवी को एमपॉवर करना, देश के सामान्य नागरिक को एमपॉवर करना, उस पर बल दे रहे हैं और मैं एक बात देशवासियों के सामने नम्रतापूवर्क कहना चाहता हूं कि मैं अपने वर्तमान की चिंता में, मैं अपने वर्तमान की चिंता में देश के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकता हूं।

'मुद्रा योजना' से, बिना बैंक गारंटी 9 करोड़ से ज्यादा खाता धारकों को पौने चार लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज दिया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं बिना गारंटी 9 करोड़ लोगों को पौने चार करोड़ रुपया और इन 9 करोड़ में से 2 करोड़ 63 लाख नौजवान ऐसे हैं, जिन्होंने पहली बार बैंकों से कारोबार के लिए 'मुद्रा योजना' से ये धन पाया है, कर्ज लिया है।

उन्होंने कहा कि इस सरकार ने प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के साथ पर्सनल सेक्टर पर भी जोर दिया है। वरना हमारे देश में दो ही प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इसी की चर्चा हो रही थी। एक और भी आयाम है पर्सनल सेक्टर, उसका भी उतना ही तवज्जो होना चाहिए। पर्सनल सेक्टर, जो लोगों की पर्सनल एस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है और इसलिए ये सरकार ऐसे नौजवानों को हर संभव मदद दे रही है, जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि 'मुद्रा योजना' से, बिना बैंक गारंटी 9 करोड़ से ज्यादा खाता धारकों को पौने चार लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज दिया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं बिना गारंटी 9 करोड़ लोगों को पौने चार करोड़ रुपया और इन 9 करोड़ में से 2 करोड़ 63 लाख नौजवान ऐसे हैं, जिन्होंने पहली बार बैंकों से कारोबार के लिए 'मुद्रा योजना' से ये धन पाया है, कर्ज लिया है।

श्री मोदी ने कहा कि सरकार, स्किल इंडिया मिशन, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से भी स्वरोजगार

को बढ़ावा दे रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉर्मल सेक्टर में लाने के लिए कंपनियों को आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि फॉर्मल सेक्टर में रोजगार के कुछ इंडीकेटर्स को देखें, तो मार्च 2014 के अंत में ऐसे 3 करोड़ 26 लाख कर्मचारी थे, जो सक्रिय रूप से Employees Provident Fund Organization में हर महीने PF का पैसा जमा करा रहे थे। ये आंकड़ा याद रखना। पिछले तीन साल में ये संख्या बढ़ करके 4 करोड़ 80 लाख पहुंच गई है। कुछ लोग, शल्य- यह भी ये भूल जाते हैं कि बिना रोजगार बढ़े ये संख्या कभी बढ़ती नहीं है।

श्री मोदी ने कहा कि हम सारी योजनाओं को उस दिशा की तरफ ले जा रहे हैं जो गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की जिंदगी में गुणात्मक सुधार लाए। जनधन योजना के तहत अब तक 30 करोड़ से ज्यादा गरीबों के बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं, 'उज्ज्वला योजना' के तहत 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है, लगभग 15 करोड़ गरीबों को सरकार की बीमा योजनाओं के दायरे में लाया गया है। कुछ दिन पहले ही हर गरीब को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के लिए 'सौभाग्य योजना' की शुरुआत की गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सरकार की सारी योजनाएं गरीबों को सशक्त कर रही हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी चीज से होता है, तो वो है भ्रष्टाचार, वो है कालाधन। भ्रष्टाचार और कालेधन पर रोक लगाने में आपके संस्थान और देश की कंपनी सेक्रेटरीज की बहुत बड़ी भूमिका है। नोटबंदी के बाद जिन तीन लाख संदिग्ध कंपनियों के बारे में पता चला था, जिनके माध्यम से कालेधन का लेन-देन किए जाने की आशंका है, उनमें से 2 लाख 10 हजार कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। हमारे देश में एक कम्पनी भी अगर बंद करो तो काले झंडों के जुलूस निकलते हैं। 2 लाख 10 हजार की हैं, कोई समाचार ही नहीं आ रहा है। न कोई मोदी का पुतला जला रहे हैं, यानी कितनी झूठी दुनिया चली होगी, आप कल्पना कर सकते हैं?

श्री मोदी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि नकली कंपनियों के खिलाफ इस सफाई अभियान के बाद डायरेक्टरों में भी जागरूकता बढ़ेगी और इसके असर से कंपनियों में पारदर्शिता भी आएगी और आप उस भूमिका को बहुत अच्छी तरह निभाएंगे। देश के इतिहास में ये कालखंड बहुत बड़े परिवर्तन का है, बहुत बड़े बदलाव का है। देश में ईमानदार और पारदर्शी शासन का महत्व समझा जाने लगा है। कोर्पो दर गवर्नेंस फ्रेमवर्क के निर्धारण के समय ICSI की सिफारिशों की काफी सकारात्मक भूमिका रही थी। अब समय की मांग है कि आप एक नया बिज़नेस कल्चर पैदा करने में भी सक्रिय भूमिका निभाएं।

उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद इनडायरेक्ट टैक्स के दायरे में 19 लाख नए नागरिक आए हैं। छोटा व्यापारी हो या बड़ा, जीएसटी में समाहित ईमानदार व्यवस्था को अपनाए, इसके लिए व्यापारी वर्ग को प्रेरित करते रहना, ये मेरी आप सबसे अपेक्षा है।

श्री मोदी ने कहा कि 2022 में देश आजादी के 75 साल मनाएगा और हमारे दिल में एक सपना होना चाहिए कि जिन महापुरुषों ने देश की आजादी के लिए अपनी जवानी खपा दी, मौत को गले लगाया, जिंदगी जेलों में बिता दी, आजीवन संघर्ष करते रहे, मां भारती के लिए अनेक सपने देखे हुए थे। 2022 में उस आजादी के 75 साल हो रहे हैं। हर हिन्दुस्तानी के लिए 2022 ऐसा ही सपना होना चाहिए कि 1942 में 'भारत छोड़ो आंदोलन' के समय देशवासियों के अंदर ज्वार आया था कि अब तो अंग्रेजों को निकाल कर रहेंगे। हम भी 2022, 75 साल के लिए ऐसे कुछ सपनों को ले करके चलें।

श्री मोदी ने कहा कि क्या आपका संस्थान, अगर मैं उनसे कुछ वादा चाहूं, मैं नहीं चाहता हूं आज ही मुझे हां कर दीजिए, लेकिन आप सोचिए, क्या आप 2022 तक कुछ संकल्प ले सकते हैं क्या? वो वादों में आपके संकल्प होंगे और उन संकल्पों को आप ही को सिद्ध करना होगा। क्या आप 2022 तक देश को एक हाई टैक्स कॉम्प्लिएंट सोसाइटी बनाने का बीड़ा उठा सकते हैं?

उन्होंने कहा कि क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि 2022

नोटबंदी के बाद जिन तीन लाख संदिग्ध कंपनियों के बारे में पता चला था, जिनके माध्यम से कालेधन का लेन-देन किए जाने की आशंका है, उनमें से 2 लाख 10 हजार कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है। हमारे देश में एक कम्पनी भी अगर बंद करो तो काले झंडों के जुलूस निकलते हैं। 2 लाख 10 हजार की हैं, कोई समाचार ही नहीं आ रहा है।

तक देश में एक भी नकली कंपनी नहीं रहेगी? क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि 2022 तक देश में हर कंपनी ईमानदारी से टैक्स भरेगी? तालियां कम हो गईं, वो कठिन कार्य था। क्या आप अपनी मदद का दायरा बढ़ाकर 2022 तक देश में एक ईमानदार बिज़नेस कल्चर स्थापित कर सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि 49 साल की यात्रा आपने पूरी की है। स्वर्ण जयंती वर्ष की शुरुआत है। ICSI इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अलग से कुछ दिशा-निर्देश तय करेगा और उन्हें अपनी कार्य संस्कृति में भी शामिल करेगा।

उन्होंने कहा कि देश में जो एक पैरामीटर मैंने दिखाया, ऐसे कई पैरामीटर हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती का सबूत देते हैं, सरकार की निर्णय शक्ति का सबूत देते हैं। सरकार की दिशा और गति का सबूत देते हैं और देश और दुनिया में भारत के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, उसकी भली-भांति उसमें ताकत नजर आती है। इसको हम नजरअंदाज न करें और हम नए भारत के निर्माण के लिए नया उत्साह, नया विश्वास, नई उमंग, नई संस्कृति लेकर चल पड़ें। ■

विमुद्रीकरण और जीएसटी का मंदी प्रभाव कमोबेश समाप्तः अरुण जेटली

वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने 13 अक्टूबर को अमेरिका में फिक्की द्वारा आयोजित 'इंडिया अपॉरचुनिटी' पर चर्चा-सम्मेलन में हिस्सा लिया। श्री जेटली ने भारत में चलने वाले महत्वपूर्ण सुधारों पर बोलते हुए कहा कि इन सुधारों से संरचना परिसंपत्तियों में अनेक अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित ढांचागत सुधारों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत, सतत और संतुलित विकास की ओर उन्मुख है। इसके अलावा ऐसे प्रमाण भी मिल रहे हैं कि विमुद्रीकरण और जीएसटी के मंदी प्रभाव कमोबेश समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। भारत सरकार द्वारा उठाए जाने वाले सुधारात्मक कदमों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास गति तेज हो चुकी है। श्री जेटली ने कहा कि 2015-16 की तुलना में 2016-17 के दौरान सीधा विदेशी निवेश बढ़ गया है, जिससे पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है।

जी-20 को विश्व अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रयास करना होगा

वित्त एवं कारपोरेट मामलो के मंत्री श्री अरुण जेटली ने 13 अक्टूबर को वॉशिंगटन डीसी में आयोजित जी-20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान विश्व अर्थव्यवस्था और विकास रूप-रेखा, अफ्रीका के साथ संबद्धता और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना पर चर्चा की गई।

जी-20 रूपरेखा कार्य समूह (एफडब्ल्यूजी) के सह-अध्यक्ष के रूप में भारत ने 'विश्व अर्थव्यवस्था और विकास रूप-रेखा' पर दूसरे दौर के सत्र के दौरान प्रमुख हस्तक्षेप किया था। इस दौर में 'मजबूत, टिकाऊ और संतुलित विकास' (एसएसबीजी) पर आईएमएफ जी-20 रिपोर्ट पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि यह रिपोर्ट विश्व अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियों को समझने और उनके लिए जी-20 की कारगर प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए उपयोगी सामग्री प्रदान करती है। वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि सदस्य देशों की घरेलू नीतिगत गतिविधियों के वैश्विक प्रभावों को समझना बहुत आवश्यक है। इसके संबंध में खासतौर से कारोबारी और वित्तीय नियमों को ध्यान में रखना होगा।

उन्होंने सुझाव दिया कि आईएमएफ एसएसबीजी रिपोर्ट को संभावित विश्लेषक उपायों की परख के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि उनके द्वारा नीति प्रभावों को समझा जा सके। उन्होंने कहा कि इसे संभव बनाने के लिए सदस्यों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हर देश की नीति को स्पष्ट रूप से पेश किया जाए और प्रमुख चुनौतियों के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई को

आपस में साझा किया जाए। ऐसा करने से चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझने में सहायता होगी, जो सभी सदस्यों के लिए लाभप्रद है।

अफ्रीका के साथ संबद्धता पर जी-20 सत्र के दौरान विभिन्न विषयों तथा अफ्रीका सलाहकार समूह के कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना सत्र में पूंजी प्रवाह की निगरानी, विश्व वित्तीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने और संरचना निवेश के लिए वित्त पोषण के संबंध में एमडीबी की क्षमता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

समूची वैश्विक वित्तीय प्रणाली को साइबर से खतरा

केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 15 अक्टूबर को वाशिंगटन डीसी में आईएमएफसी के प्रतिबद्ध ब्रेकफास्ट सत्र में भाग लिया। परिचर्चा सत्रों के दौरान नीतिगत चुनौतियों से जुड़ी वार्ता पर फोकस किया गया। इस वर्ष और अगले वर्ष वैश्विक आर्थिक आउटलुक के आश्वासनपूर्ण रहने के आसार को ध्यान में रखने के साथ-साथ श्री जेटली ने मध्यम अवधि में सावधानी बरतने की सलाह को भी ध्यान में रखा। उन्होंने पूर्व चेतावनी के तहत साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किए जाने की सराहना की और इस बात पर विशेष जोर दिया कि समूची वैश्विक वित्तीय प्रणाली को इससे खतरा है क्योंकि यह आपस में काफी अधिक जुड़ गई है।

इस संबंध में वित्त मंत्री ने तीन नीतिगत चुनौतियों पर प्रकाश डाला। पहली चुनौती यह है कि सामान्य मौद्रिक स्थिति बहाल करने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा उठाए जा रहे साहसिक कदमों से उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के समक्ष जोखिम उत्पन्न हो गए हैं। दूसरी चुनौती निवेश में वैश्विक सुस्ती और तीसरी चुनौती रोजगार को लेकर है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता हर साल श्रम बल में शामिल होने वाले 12 मिलियन युवाओं को रोजगार देने के तरीके ढूंढना है। ■

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 4.9 प्रतिशत बढ़ा

अगस्त, 2017 में आठ कोर उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 123.6 प्रतिशत रहा, जो अगस्त 2016 के मुकाबले 4.9 प्रतिशत ज्यादा है। वहीं, वर्ष 2017-18 की अप्रैल-अगस्त की अवधि के दौरान संचयी उत्पादन वृद्धि दर 3.0 प्रतिशत रही।

कोयला

अगस्त, 2017 में कोयला उत्पादन (भारांकः 10.33%) रहा, जो अगस्त, 2016 के मुकाबले 15.3 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-अगस्त, 2017-18 में इसके संचयी सूचकांक में बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना 0.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

बिजली

अगस्त, 2017 के दौरान बिजली उत्पादन (भारांकः 19.85%) में अगस्त, 2016 के मुकाबले 10.3 प्रतिशत का इजाफा हुआ। अप्रैल-अगस्त, 2017-18 में इसका संचयी सूचकांक बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.5 प्रतिशत अधिक रहा।

प्राकृतिक गैस

अगस्त 2016 की तुलना में अगस्त, 2017 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन (भारांकः 6.88%) 4.2 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल-अगस्त, 2017-18 में इसके संचयी सूचकांक में बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

रिफाइनरी उत्पाद

अगस्त 2016 की तुलना में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन (भारांकः 28.04%) अगस्त, 2017 में 2.4 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल-अगस्त, 2017-18 में इसका संचयी सूचकांक बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में 1.0 प्रतिशत अधिक रहा।

इस्पात

अगस्त 2016 की तुलना में अगस्त, 2017 में इस्पात उत्पादन (भारांकः 17.92%) 3.0 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल-अगस्त, 2017-18 में इसका संचयी सूचकांक बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.0 प्रतिशत अधिक रहा।

सीमेंट

अगस्त, 2017 के दौरान सीमेंट उत्पादन (भारांकः 5.37%) जून, 2016 के मुकाबले 1.3 प्रतिशत कम रहा। अप्रैल-अगस्त, 2017-18 में इसका संचयी सूचकांक बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.3 प्रतिशत कम रहा।

नोट 1: जून, 2017, जुलाई, 2017 और अगस्त, 2017 के आंकड़े अंतरिम हैं।

नोट 2: अप्रैल, 2014 से ही बिजली उत्पादन के आंकड़ों में नवीकरणीय अथवा अक्षय स्रोतों से प्राप्त बिजली को भी शामिल किया जा रहा है। ■

सितंबर में 25 प्रतिशत बढ़ा निर्यात

देश के निर्यात की वृद्धि दर सितंबर महीने में 6 महीने के उच्चचम स्तर 25.7 प्रतिशत पर रही। यह दूसरा महीना है जब निर्यात वृद्धि दर दो अंकों में रही है। प्रसंस्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करीब 40 प्रतिशत बढ़ा है। इसके अलावा निर्यात के प्रमुख सामानों में इंजीनियरिंग के सामान और रत्न एवं आभूषण विदेशी मुद्रा की कमाई के मुख्य स्रोत हैं। वहीं, दूसरी ओर आयात की वृद्धि दर में गिरावट आई है। सितंबर में आयात वृद्धि अगस्त के 21 प्रतिशत की तुलना में घटकर 18 प्रतिशत रह गई। देश में करीब 37.59 अरब डॉलर का सामान भारत आया।

इसकी वजह से व्यापार घाटा सितंबर महीने में 8.98 अरब डॉलर रहा। सितंबर 2016 में कारोबारी घाटा 9.07 अरब डॉलर था। गैर तेल और गैर स्वर्ण आयात 19.76 प्रतिशत बढ़ा है। इससे औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर लगातार दूसरे महीने बेहतर रहने की उम्मीद है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) अगस्त में 4.2 प्रतिशत बढ़ा है। निर्यात में लगातार 13वें महीने में बढ़ोतरी हुई है। देश से सितंबर महीने में 28.61 अरब डॉलर के सामान का निर्यात हुआ है, जो पिछले साल की समान अवधि में 22.76 अरब डॉलर था। गैर तेल निर्यात सितंबर महीने में 23.88 प्रतिशत बढ़ा है, जो अगस्त के 6.86 प्रतिशत से ज्यादा है। ■

गांवों को स्वावलम्बी बनाने हेतु समर्पित थे नानाजी देशमुख : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर को पूसा, नई दिल्ली स्थित आईएआरआई में नानाजी देशमुख के जन्म शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने नानाजी देखमुख और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने नानाजी देशमुख के सम्मान में डाक टिकट जारी किया।

उन्होंने कहा कि आज हम दो महान नेताओं–नानाजी देशमुख और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस मना रहे है, जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र की बेहतरी के लिए अर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण युवाओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के आह्वान से प्रेरित होकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉ. लोहिया 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के दौरान सक्रिय हुए। उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सत्ता की राजनीति में कभी रुचि नहीं दिखाई और वे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते रहे। उन्होंने कहा कि नानाजी देशमुख ने भी ग्रामीण विकास और हमारे गांवों को स्वावलम्बी व निर्धनता से मुक्त करने की दिशा में स्वयं को अर्पित कर दिया।

उन्होंने कहा कि आज मुझे खुशी है कि नानाजी के जन्मशती के अवसर पर भारत सरकार इन महापुरुषों के सपनों के आधार पर और महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर ग्रामीण विकास की

भारत के ग्रामीणों की सेवा और सशक्तिकरण के लिए एक नागरिक केन्द्रित मोबाइल ऐप 'ग्राम संवाद' का शुभारम्भ किया, जिसमें नागरिक विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में ग्राम पंचायत स्तर पर एकल विंडो पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप में इस समय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सात कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।

दिशा में हम कैसे आगे बढ़ें, हमारे गांव आत्मनिर्भर कैसे बने, हमारे गांव गरीबी से मुक्त कैसे बने, हमारे गांव बीमारी से मुक्त कैसे बने, हमारे गांव जिसमें आज भी जातिवाद का जहर गांव को बिखेर देता है, गांव के सपनों को चूर-चूर कर देता है, उस जातिवादी भावनाओं से

ऊपर उठ करके गांव एक समृद्ध गांव बने, सबको जोड़ने वाला गांव बने और सब मिल करके गांव के कल्याण के लिए संकल्प करे। उस प्रकार के गांव के विकास को जन भागीदारी से आगे बढ़ाने की दिशा में भारत सरकार अनेक कदम उठा रही है।

श्री मोदी ने कहा कि आज मुझे यहां पर देश के ग्रामीण जीवन के लिए सोचने वाले, ग्रामीण जीवन के लिए योगदान देने वाले, ग्रामीण अर्थकारण का, ग्रामीण कृषि जीवन का ऐसे भिन्न-भिन्न विषयों पर जिनकी महारथ है, ऐसे देश के तीन सौ से ज्यादा लोग कल पूरे दिन बैठे, अलग-अलग गुटों में बैठे, आधुनिक संदर्भ में गांव का विकास कैसे हो, उसका विचार-विमर्श किया और पूरे दिन भर इन अनुभवी लोगों ने जो मंथन किया है। उससे जो अमृत निकला है, आज अभी एक वीडियो के माध्यम से उसे प्रस्तुत करने का भी प्रयास हुआ, लेकिन मैं इन सब महानुभावों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो विचार-विमर्श किया है, मंथन किया है और जो बिंदु छांट करके आपने निकाले हैं भारत सरकार उसको गौर करेगी, गंभीरता से लेगी।

उन्होंने ने कहा कि स्वच्छता आज गांव का स्वभाव बन रहा है। गांव भी जिम्मेदारी को लेने लगे हैं। हमारे कई गांव आजादी के 70 साल बाद भी, 18 हजार गांव ऐसे, जो आज भी 18वीं शताब्दी में जीते हैं। न बिजली का खम्भा है, न बिजली का लट्टू है, न गांव में कभी बिजली देखी है। हमने बीड़ा उठाया, लाल किले से कहा एक हजार दिन में 18 हजार गांव में बिजली पहुंचाएंगे और मुझे खुशी है कि राज्य सरकारों ने भी उसमें हाथ बंटाया, भारत सरकार ने भी उसमें तेजी लाई और आज बहुत तेजी से 18 हजार गांव के उस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। करीब-करीब 15 हजार गांव में बिजली पहुंच गई है। अब गांवों में बिजली पहुंच गई तो हम

वहां अटकने वाले नहीं हैं।

श्री मोदी ने कहा कि अब हमारा सपना है गांव हो या शहर घर हो या झोपड़ी हरेक के घर में बिजली का लट्टू होना चाहिए। 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, बड़ा बीड़ा उठाया है और इसलिए गरीब परिवारों को घर में कनेक्शन देने के लिए पहले पैसे देने पड़ते थे। हमने तय किया है मुफ्त में कनेक्शन देंगे, बिजली पहुंचाएंगे और मुझे विश्वास है कि एक बार बिजली आई तो घर के जीवन में भी बदलाव आएगा, बच्चों को शिक्षा के लिए सुविधा बढ़ेगी। घर का जीवन बदलेगा, 24 घंटे बिजली देने का निर्धारित लक्ष्य के साथ काम करने की दिशा में आज हम आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने ने 'प्रौद्योगिकी और ग्रामीण जीवन' विषय पर एक प्रदर्शनी भी देखी। उन्होंने अच्छी पद्धति एवं उनके अनुकरण के साथ-साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं व पहल को भी देखा। उन्होंने कुछ अन्वेषकों व लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया।

उन्होंने ने दिशा पोर्टल का भी शुभारम्भ किया–जो सांसदों और विधायकों के लिए अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं के कार्यान्वयन पर एकल पोर्टल के माध्यम से निगरानी रखने का पोर्टल है। अभी तक 20 मंत्रालय के 41 कार्यक्रमों व योजनाओं की प्रगति के आंकड़े इस पोर्टल पर दर्शाए गए हैं।

उन्होंने भारत के ग्रामीणों की सेवा और सशक्तिकरण के लिए एक नागरिक केन्द्रित मोबाइल ऐप 'ग्राम संवाद' का शुभारम्भ किया, जिसमें नागरिक विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में ग्राम पंचायत स्तर पर एकल विंडो पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस ऐप में इस समय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सात कार्यक्रमों को शामिल किया गया है।

उन्होंने ने 11 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान भवनों (आरएसईटीआई) तथा आईएआरआई में प्लान्ट फिनोमिक्स सुविधा का डिजिटल पद्धति से उद्घाटन किया। उन्होंने ने स्वयं सहायता समूहों, पंचायतों, जल संरक्षण अन्वेषकों और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के 10,000 से ज्यादा लोगों को सम्बोधित किया। ■

जवानों को दिवाली का तोहफा

500 रुपये का मासिक डीएसपीटी शुल्क 'शून्य'

विभिन्न सैन्य बलों और सीआरपीएफ, बीएसएफ, बीआरओ, आईटीबीपी जैसी विभिन्न अर्द्धसैनिक इकाइयों के जवान और अधिकारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए दूर-दराज तथा दुर्गम स्थानों पर तैनात हैं। ये जवान और अधिकारी कठिन मौसम की परवाह किए बिना दिन-रात देश की सुरक्षा में लगे हैं। ये सभी अपने घरों और मुख्यालयों से दूर सेवा कर रहे हैं। अपने घरवालों और अपने मुख्यालयों के साथ बातचीत करने की उन्हें हमेशा आवश्यकता होती है। ये सभी बीएसएनएल द्वारा प्रदत्त डीएसपीटी सेवा के जरिए ही संपर्क करते हैं, क्योंकि इन इलाकों में संचार का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध नहीं है।

संचार मंत्री श्री मनोज सिंहा ने 18 अक्टूबर को मीडिया से बात करते हुए कहा कि डीएसपीटी सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए जवानों और अधिकारियों को इस समय हर माह 500 रुपये का शुल्क देना पड़ता है। इस तरह उन्हें प्रति मिनट की बातचीत के लिए 5 रुपये देने पड़ते हैं। जवानों और अधिकारियों की आवश्यकताओं को देखते हुए और संचार में होने वाले भारी खर्च के मद्देनजर सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, ताकि परिवार वालों से बातचीत करने में जवानों और अधिकारियों को सुविधा हो। यह अहम फैसला दीपावली के शुभ अवसर पर लिया गया है। श्री सिन्हा ने कहा कि दीपावली के दिन यानी 19 अक्टूबर, 2017 से डीएसपीटी सुविधा के लिए कोई भी मासिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी कल से मौजूदा 500 रुपये

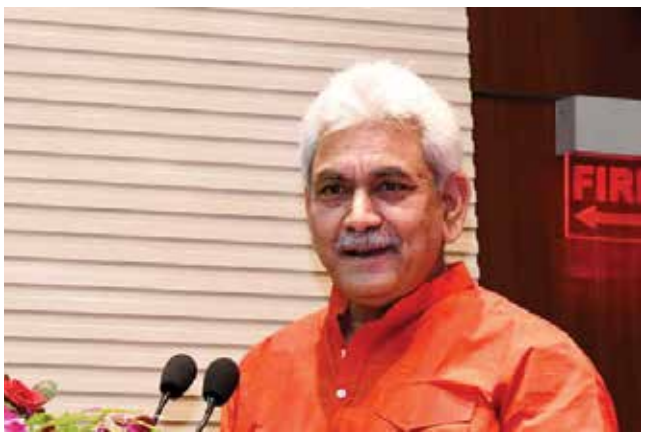

का मासिक शुल्क 'शून्य' हो जाएगा। इसके अलावा मौजूदा 5 रुपये प्रति मिनट के लिए लिया जाने वाला टेलीफोन शुल्क भी एक रुपया प्रति मिनट हो जाएगा।

सरकार के इस विशेष दीपावली उपहार के आधार पर सुरक्षाकर्मी अब अपने घरों और मुख्यालय के साथ बिना किसी चिंता तथा अतिरिक्त खर्च किए बिना बात कर सकेंगे। मंत्री महोदय ने जवानों और अधिकारियों तथा उनके परिवार वालों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दीं। ■

'ज्ञान' और 'गंगा' दोनों से समृद्ध है बिहार: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अक्टूबर को पटना विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वह पटना विश्वविद्यालय में आने और छात्रों के बीच होने को अपना सम्मान मानते हैं। श्री मोदी ने कहा, 'मैं बिहार की इस धरती को नमन करता हूं। इस विश्वविद्यालय ने ऐसे छात्रों को तैयार किया, जिन्होंने देश में काफी योगदान दिया है।'

उन्होंने कहा कि बिहार 'ज्ञान' और 'गंगा' दोनों से समृद्ध है। उन्होंने कहा कि यह भूमि एक विरासत है जो अनोखी है। उन्होंने कहा कि हमारे विश्वविद्यालयों को पारंपरिक शिक्षण से नवोन्मेषी शिक्षा की ओर अग्रसर होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमंडलीकरण के इस दौर में हमें दुनिया भर में बदलते रुझानों और प्रतिस्पर्धा की बढ़ती भावना को समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उसी संदर्भ में भारत को दुनिया में अपनी जगह बनानी होगी।

उन्होंने कहा कि उन्होंने विभिन्न राज्यों में देखा है कि शीर्ष स्तर के सिविल सेवा में वही लोग हैं, जिन्होंने पटना विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। उन्होंने कहा, 'दिल्ली में मैं इतने सारे अधिकारियों से बातचीत करता हूं, जिनमें से कई बिहार से ताल्लुख रखते हैं।' श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता सराहनीय है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वी भारत के विकास को सबसे अधिक महत्व देती है।

उन्होंने छात्रों से कहा कि उन्हें लोगों के सामने आने वाली समस्याओं के लिए अभिनव समाधान के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो सीखा उसे लागू करते हुए और स्टार्टअप क्षेत्र के जरिये वे समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। गौरतलब है कि पटना विश्वविद्यालय से हवाई अड्डे तक वापस जाते हुए रास्ते में प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य लोगों ने बिहार संग्रहालय का दौरा किया जो राज्य की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को प्रदर्शित करता है।

प्रधानमंत्री ने चार सीवरेज और चार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के मोकामा में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत चार सीवरेज परियोजनाओं और चार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं का कुल परिव्यय 3,700 करोड़ रुपये से अधिक है। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महान कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के साथ करीबी से जुड़ी धरती पर आकर उन्हें खुशी हो रही है। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार बिहार के विकास के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की आधारशिला आज रखी जा रही है उनसे बिहार के विकास को

गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क निर्माण की रफ्तार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे से संबंधित परियोजनाएं गंगा नदी को बचाने में मदद करेंगी।

हाल में शुरू किए गए अंत्योदय एक्सप्रेस का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इनसे बिहार, पूर्वी भारत और देश के अन्य भागों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। अच्छी कनेक्टिविटी से बेहतर विकास होने पर जोर देते हुए उनहोंने कहा कि सड़क, रेलवे और जलमार्ग पर जोर दिया जा रहा है। जिन चार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखी गई है उनमें शामिल हैं:

- राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के अंटा-सिमरिया खंड को 4 लेन बनाना और 6 लेन वाला गंगा सेतु का निर्माण
- राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के बख्तियारपुर-मोकामा खंड को 4 लेन बनाना
- राष्ट्रीय राजमार्ग 107 के महेशखूंट-सहरसा-पूर्णिया खंड पर 2-लेन का निर्माण
- एनएच 82 के बिहारशरीफ-बरबिघा-मोकामा खंड पर 2-लेन का निर्माण

चार सीवरेज परियोजनाओं में बेऊर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बेऊर में सीवर नेटवर्क के साथ सिवरेज प्रणाली, करमालीचक में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सैदपुर में एसटीपी एवं सीवर नेटवर्क शामिल हैं। इन परियोजनाओं से कुल मिलाकर 120 एमएलडी नई एसटीपी क्षमता सृजित होगी और बेऊर के लिए मौजूदा 20 एमएलडी का उन्नयन होगा। ■

पत्र-पत्रिकाओं से...

कश्मीर में बड़ी पहल

स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह घोषणा किए जाने के बाद कश्मीर में राजनीतिक पहल की संभावना बढ़ गई थी कि घाटी की समस्या का हल गाली और गोली से नहीं, बल्कि कश्मीरियों को गले लगाने से होगा। कुछ देर से ही सही, केंद्रीय सत्ता ने सभी पक्षों से बात करने के लिए खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख दिनेश्वर शर्मा को अपने प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त कर यह स्पष्ट कर दिया कि वह कश्मीर समस्या के स्थाई समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता की झलक इससे मिलती है कि दिनेश्वर शर्मा को कैबिनेट सचिव का दर्जा देने के साथ ही यह तय करने का अधिकार भी दिया गया है कि वह जिससे चाहें उससे वार्ता कर सकते हैं।

— (दैनिक जागरण, 14 अक्टूबर)

आयुर्वेद को संजीवनी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्थिति से जुड़ा एक और अहम सवाल उठाया। पूछा कि जो लोग आज आयुर्वेद पढ़कर निकलते हैं, क्या वे सचमुच 100 प्रतिशत इसमें आस्था रखते हैं? आम अनुभव है कि मरीज जब जल्द ठीक होने पर जोर देते हैं, तब कई मौकों पर आयुर्वेदिक चिकित्सक उन्हें एलोपैथी दवाएं दे देते हैं. दरअसल, ऐसा होने की कुछ ऐतिहासिक वजहें हैं। उनकी तरफ मोदी ने भी इशारा किया। प्राचीन भारतीय ऋषि परंपरा, आचार्यों, किसानों, देसी विज्ञान, योग, आयुर्वेद आदि का गुलामी के दौर में उपहास किया गया। प्रधानमंत्री ने 'आयुर्वेद दिवस के मौके पर इस संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया। धन्वंतरि जयंती के दिन ये दिवस मनाने की शुरुआत इसी सरकार के कार्यकाल में हुई। ऐसे में आयुर्वेद विशेषज्ञ, निजी क्षेत्र और समग्र समाज अगर इस मौके का भरपूर लाभ उठाएं, तो बेशक आयुर्वेद का युग फिर से लौट सकता है।

— नई दुनिया (18 अक्टूबर)

बढ़े देश का धन

आईएमएफ प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने नोटबंदी और जीएसटी को ऐतिहासिक प्रयास बताते हुए कहा कि इतने बड़े सुधार के कदमों के कारण कुछ समय तक आर्थिक सुस्ती की स्थिति बनना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूती हासिल करने की ओर बढ़ रही है। घाटा कम हुआ है और महंगाई भी नीचे बनी हुई है। इन संकेतों को अगर नीतिगत सुधारों से जोड़कर देखें तो भविष्य में वे नतीजे निकलते दिखेंगे, जिनकी उम्मीद भारत का युवा कर रहा है।

— (नवभारत टाइम्स, 17 अक्टूबर)

बढ़ती हुई मुहिम

स्वच्छ भारत अभियान के तीन साल पूरे हो गए। इन तीन वर्षों में स्वच्छता को लेकर समाज में एक सकारात्मक माहौल बना है। सफाई देश के अजेंडे पर आ गई है। एक सोशल मीडिया साइट 'लोकल सर्किल्स' द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार शहरों और कस्बों के करीब आधे लोगों ने माना है कि पिछले तीन वर्षों में स्वच्छ भारत स्कीम का ठीक-ठाक असर उन्हें अपने आसपास देखने को मिला है। लोग मान रहे हैं कि चीजें एकदम से तो नहीं बदली हैं, मगर सही दिशा में जा रही हैं। भारत जैसे देश में, जहां सफाई कभी मुद्दा ही नहीं रही, इसे एक जन अभियान का रूप लेने में वक्त तो लगेगा ही। असल में हमारे अचेतन में यह भाव कहीं न कहीं बैठा रहा कि सफाई करना हमारा नहीं दूसरों का काम है। इस मानसिकता पर महात्मा गांधी ने प्रहार किया था। उन्होंने स्वच्छता को एक नैतिक जवाबदेही और एक मूल्य बताया था। पर आजादी के बाद दुर्भाग्य से महात्मा गांधी के स्वप्न को भुला दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके महत्व को स्वीकार किया है और इसे अपना एक प्रमुख अजेंडा बनाया है।

— (नवभारत टाइम्स, १ अक्टूबर)

स्फुट विचार...

युगों का भारत मृत नहीं हुआ है और न उसने अपना अंतिम सृजनात्मक शब्द उच्चारित ही किया है, वह जीवित है और उसे अभी भी स्वयं अपने लिए और मानव लोगों के लिए बहुत कुछ करना है और जिसे अब जागृत होना आवश्यक है।

— महर्षि अरविन्द

महान उपलब्धियां कभी भी आसानी से नहीं मिलतीं और आसानी से मिली उपलब्धियां महान नहीं होतीं।

— बाल गंगाधर तिलक

समूचा भारत हमारी निष्ठाओं का केंद्र और हमारा कार्यक्षेत्र है। भारत की जनता हमारा आराध्य है। हमें अपनी स्वाधीनता को अमर बनाना है, राष्ट्रीय अखंडता को अक्षुण्ण रखना है और विश्व में स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीवित रहना है।

— अटल बिहारी वाजपेयी

हमारा उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों में समरसता लाकर उन्हें एक ऐसे संयुक्त समाज का रूप देना है जो शोषण और किसी प्रकार के उत्पीड़न से मुक्त हो।

— कुशाभाऊ ठाकरे

प्रस्तुति: पंकज आनंद

हमारे सम्मानित आजीवन सदस्यगण

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत
श्री अमित शाह
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री
श्री राधा मोहन सिंह
केंद्रीय कृषि मंत्री
श्री प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय
केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री
श्री बाबुल सुप्रियो
केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री
श्री मनोहर पर्रिकर
मुख्यमंत्री, गोवा

श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री
श्री अरुण सिंह
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव
श्री शांता कुमार, सांसद
पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपाल नारायण सिंह
सांसद (राज्यसभा)
डॉ. गोकाराजू गंगा राजू
सांसद (लोकसभा)
श्री महेश पोद्दार
सांसद (राज्यसभा)
श्री अनिल शिरोले
सांसद (लोकसभा)
श्री मनोज राजोरिया
सांसद (लोकसभा)
श्री रवींद्र कुमार राय
सांसद (लोकसभा)
श्री दिलीप कुमार गांधी
सांसद (लोकसभा)
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

उत्तराखण्ड स्थित केदारनाथ मंदिर में पूजा–अर्चना करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

केदारनाथ में लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

केदारनाथ में जनसभा को सम्बोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

जम्मू–कश्मीर में नियंत्रण रेखा के समीप गुरेज़ घाटी में भारतीय सेना और बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

पटना विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह के अवसर पर जनाभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, साथ में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और अन्य वरिष्ठ नेतागण

नई दिल्ली में दूसरे आयुर्वेद दिवस पर प्रथम अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्र समर्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

Power – Transmission Lines Addition (CKM)

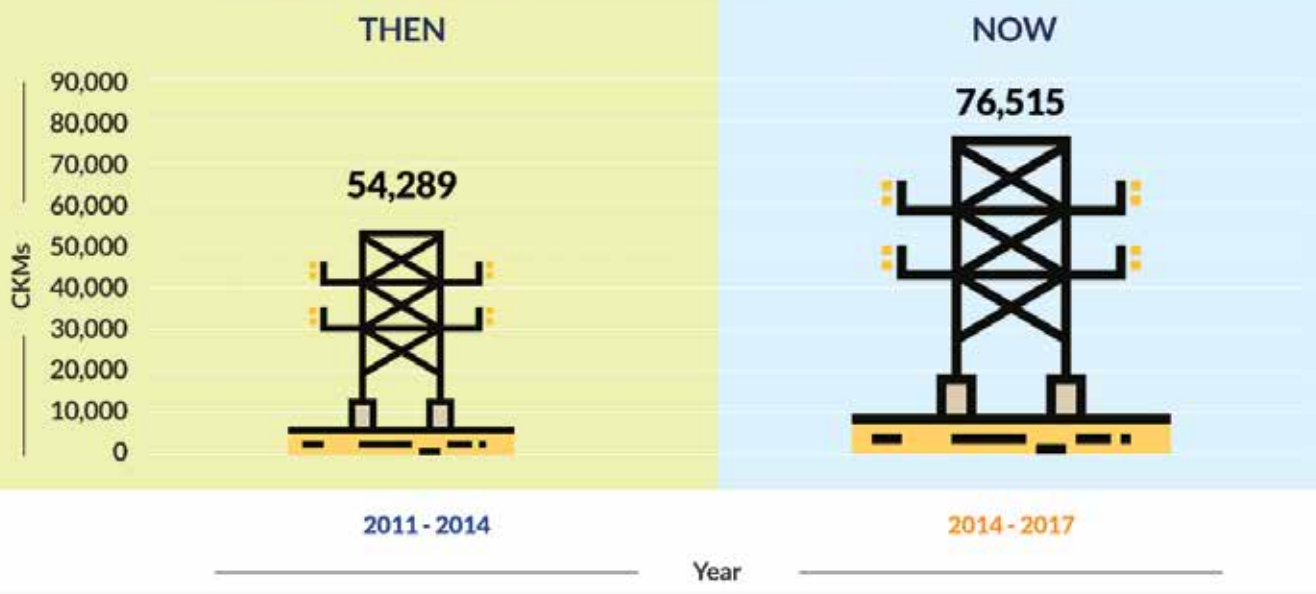

PM Modi addressing ICSI gathering on 4th October 2017

Construction of Houses

Investment in Projects (in Crore)

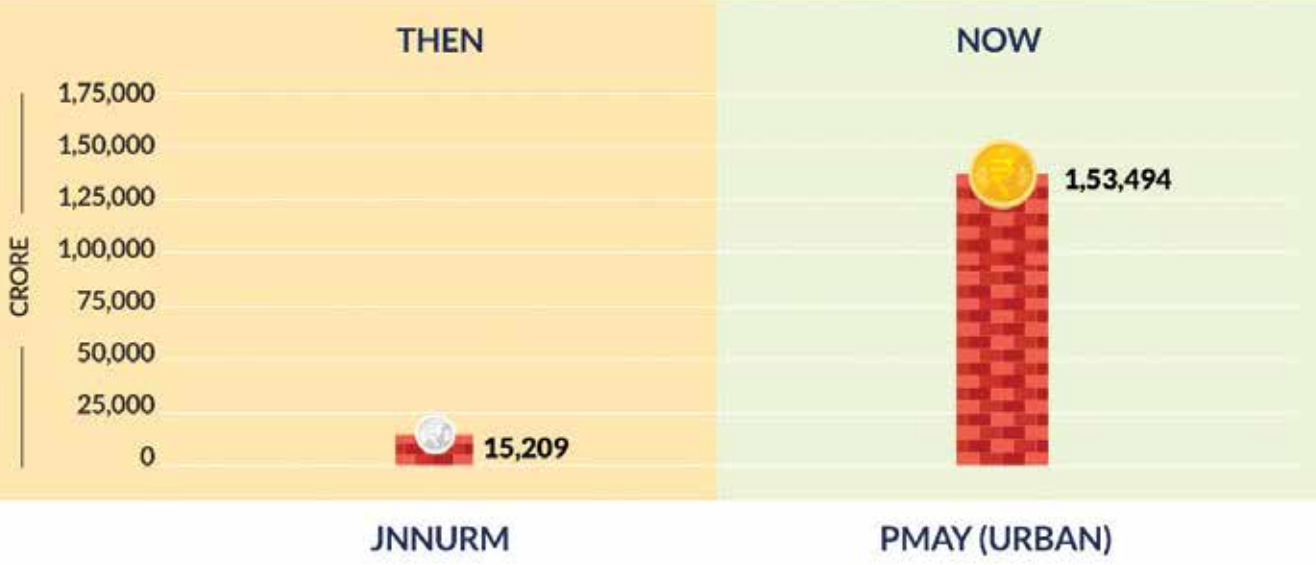

PM Modi addressing ICSI gathering on 4th October 2017